राष्ट्रीय हिन्दी दैनिक

क्रांति समय

कार्यालय ऑफिस

क्रांति समय
दैनिक समाचार में
प्रेसनोट, नोटिस, वेपार संबंधित संपर्क करें
संपर्क नं.-7490923915
ईमेल:-info.krantisamay@gmail.com

सुरत गुजरात से प्रकाशित, मुंबई, उत्तरप्रदेश, बिहार, राजस्थान, मध्यप्रदेश, उत्तरांचल, उत्तराखंड, दिल्ली, हरियाणा में प्रकाशित

सुरत-गुजरात, संस्करण शुक्रवार 11 सितंबर 2026 वर्ष-9,अंक-220 पृष्ठ-08 मूल्य-01 रूपये

Website : www.krantisamay.com & epaper.krantisamay.com www.facebook.com/krantisamay1 www.twitter.com/krantisamay1

पहला कॉलम

ब्रिक्स समिट में शामिल होने भारत आ रहे पुतिन, 11 को पीएम मोदी के साथ करेंगे बैठक

बातचीत में व्यापार, आर्थिक सहयोग, परिवहन और कारोबार बढ़ाने जैसे मुद्दे शामिल होंगे

नई दिल्ली।

रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ब्रिक्स समिट में शामिल होने भारत आएंगे। नई दिल्ली में 12 सितंबर को ब्रिक्स नेताओं की बैठक से पहले 11 सितंबर को पीएम मोदी और पुतिन के बीच द्विपक्षीय मुलाकात होगी। रूसी राष्ट्रपति कार्यालय क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने पीएम मोदी और पुतिन की मुलाकात की पुष्टि की है। उन्होंने कहा कि रूस भारत को अपना रणनीतिक साझेदार मानता है और दोनों देशों के रिश्ते उसके लिए बेहद अहम हैं।

पेस्कोव के मुताबिक मोदी और पुतिन की बातचीत में व्यापार, आर्थिक सहयोग, परिवहन और दोनों देशों के बीच कारोबार बढ़ाने जैसे मुद्दे शामिल होंगे। दोनों देश अपनी कंपनियों के लिए नए कारोबारी मौके तलाशने पर भी चर्चा कर सकते हैं। मोदी और पुतिन की बैठक में रूस-यूक्रेन युद्ध भी चर्चा हो सकती है। दोनों नेता युद्ध की मौजूदा स्थिति और उसके वैश्विक असर पर बातचीत कर सकते हैं। इसके अलावा फारस की खाड़ी में जारी तनाव पर भी चर्चा की संभावना है। रूस के मुताबिक खाड़ी में हो रही घटनाओं का असर वैश्विक अर्थव्यवस्था पर पड़ रहा है। ऐसे में दोनों नेताओं के बीच क्षेत्रीय तनाव और उसके आर्थिक प्रभावों पर भी बात हो सकती है।

बैठक में रक्षा सहयोग भी अहम मुद्दा रहेगा। रूस भारत को अपना एसयू-57 लड़ाकू विमान बेचने पर चर्चा करेगा। क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने कहा है कि भारत को एसयू-57 देने का मुद्दा रूस के एजेंडे में शामिल है। एसयू-57 रूस का पांचवीं पीढ़ी का लड़ाकू विमान है। इसमें स्टील्थ तकनीक है, यानी इसे रडार पर पकड़ना मुश्किल होता है। यह हवा में और जमीन पर मौजूद लक्ष्यों पर हमला कर सकता है। इसमें आधुनिक रडार और सेंसर

भी लगे हैं। भारत और रूस पहले से ब्रह्मोस मिसाइल समेत कई रक्षा परियोजनाओं पर साथ काम कर रहे हैं।

सुपरमैसिव ब्लैक होल ने अचानक दिखाई जबरदस्त सक्रियता

वाशिंगटन ।

हाल ही में अंतरिक्ष में एक सुपरमैसिव ब्लैक होल ने अचानक जबरदस्त सक्रियता दिखाई है। अंतरिक्ष में करीब दो दशक से शांत दिखाई दे रहे इस ब्लैक होल में भयंकर विस्फोट होता दिखाई दिया। इससे खगोल वैज्ञानिक भी अचंभित है। नासा के स्विफ्ट एक्स-रे टेलीस्कोप से मिले करीब 20 साल के आंकड़ों के विश्लेषण में वैज्ञानिकों ने पर्सियस क्लस्टर के केंद्र में स्थित ब्लैक होल से अब तक का सबसे बड़ा एक्स-रे फ्लेयर दर्ज किया है। यह ब्लैक होल एनजीसी 1275 गैलेक्सी के केंद्र में मौजूद है, जो पर्सियस क्लस्टर की सबसे चमकीली आकाशगंगाओं में शामिल है। इस घटना के करीब 300 दिन बाद शक्तिशाली रेडियो उत्सर्जन भी दर्ज किया गया। यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन की सारा केचम और उनकी टीम ने इस घटना का अध्ययन किया है। वैज्ञानिकों के मुताबिक यह खोज ब्लैक होल की एक्रीशन डिस्क और उससे निकलने वाले जेट के बीच संबंध को समझने में महत्वपूर्ण जानकारी दे सकती है। इस संबंध को खगोल वैज्ञानिक 'डिस्क-जेट कपलिंग' कहते हैं। इससे यह समझने में मदद मिल सकती है कि ब्लैक होल अपने आसपास की गैस को किस तरह निगलते हैं और उनके जेट पूरी आकाशगंगा के विकास को किस तरह प्रभावित करते हैं। इस ब्लैक होल की निगरानी पहले चंद्रा एक्स-रे टेलीस्कोप से भी की गई थी, लेकिन तेजी से होने वाले बदलावों को पकड़ना मुश्किल था। इसके बाद वैज्ञानिकों ने नासा के स्विफ्ट टेलीस्कोप से लगातार उपलब्ध आंकड़ों का इस्तेमाल किया और करीब 20 वर्षों की एक्स-रे गतिविधियों का विश्लेषण किया। शोध को 'एस्ट्रोफिजिकल जर्नल लेटर्स' में प्रकाशन के लिए स्वीकार किया गया है। वैज्ञानिकों के अनुसार फरवरी 2023 के आसपास शुरू हुए इस फ्लेयर के दौरान ब्लैक होल की एक्स-रे चमक लगभग दोगुनी हो गई। यह सक्रियता 60 दिनों से कम समय तक रही और इसमें कम से कम दो अलग-अलग तेज उभार दिखाई दिए। इनमें प्रत्येक करीब पांच दिन तक चला। वैज्ञानिकों ने यह भी जांचा कि कहीं किसी तारे के ब्लैक होल के बेहद करीब पहुंचकर टूटने से यह घटना तो नहीं हुई। ऐसी घटना को 'टाइडल डिसरप्शन इवेंट' कहा जाता है। हालांकि फ्लेयर की धीमी गति से घटती चमक को देखते हुए वैज्ञानिकों ने इस संभावना को काफी कम माना है।

ममता बनर्जी की श्रीरामपुर रैली को हाईकोर्ट की हरी झंडी, जुलूस पर लगाई रोक

कोलकाता ।

कलकत्ता उच्च न्यायालय ने पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को हुगली के श्रीरामपुर में जनसभा करने की अनुमति दे दी, लेकिन जीटी रोड पर उनके प्रस्तावित जुलूस रोक दिया है। अदालत ने यातायात बाधित होने की आशंका और पिछले निर्देशों के कथित उल्लंघनों का हवाला देकर फैसला सुनाया। न्यायमूर्ति सौगत भट्टाचार्य ने तृणमूल कांग्रेस के पूर्व विधायक असीत मजूमदार की याचिका पर सुनवाई कर महेश जगन्नाथ देव स्नानपीरी मैदान में दोपहर एक बजे से तीन बजे तक सभा की मंजूरी दी। इसमें अधिकतम 2,000 लोग शामिल हो सकते है। अदालत ने सख्त निर्देश दिए कि सभा के दौरान इसतरह के कोई भड़काऊ बयान नहीं दिए जाएं, जिनसे सांप्रदायिक तनाव पैदा हो सकता है, और पुलिस को किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए पर्याप्त संख्या में सुरक्षाकर्मी तैनात करने को कहा। बंगाल की सुवेंदु अधिकारी सरकार ने जुलूस का विरोध कर अदालत को बताया था कि जीटी रोड एक संकरी सड़क है और आवागमन के लिए खुला रखना अनिवार्य है, क्योंकि इसके आसपास अस्पताल, स्कूल और एक दमकल केंद्र स्थित हैं। सुवेंदु सरकार ने तर्क दिया था कि यह इलाका सांप्रदायिक रूप से संवेदनशील है। याचिकाकर्ता के वकील ने दलील दी थी कि अन्य राजनीतिक दल नियमित रूप से जीटी रोड पर रैलियां करते हैं, लेकिन जब बनर्जी कोई कार्यक्रम आयोजित करना चाहती हैं, तभी आपत्ति उठाई जाती है। उन्होंने मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी की हालिया रैली से जादवपुर में हुई यातायात अव्यवस्था का भी जिक्र किया।

चिनाब नदी पर बनेगा सावलकॉट डैम

श्रीनगर।

भारत ने सिंधु जल समझौते को लेकर अपने पुराने रुख में बड़ा बदलाव किया है। इस बदलाव का असर अब जम्मू-कश्मीर के विकास कार्यों पर दिखने लगा है। लंबे समय से अटके पड़े प्रोजेक्ट्स को फिर से शुरू किया जा रहा है। इसी सिलसिले में चिनाब नदी पर प्रस्तावित 1850 मेगावाट के सावलकॉट जलविद्युत प्रोजेक्ट को लेकर भारत ने एक बेहद अहम कदम उठाया है। बीते 40 साल से ये महत्वाकांक्षी परियोजना सिर्फ कागजों पर ही झूल रही थी। अब इसके जमीन पर उतरने की उम्मीदें काफी पुख्ता हो गई हैं। भारत सरकार पश्चिमी नदियों के पानी का पूरा इस्तेमाल करने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रही है। इसी कड़ी में सावलकॉट डैम के टेंडर की प्रक्रिया को गति दी गई है। सावलकॉट हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट पिछले करीब चार दशकों से कई तरह के पचड़ों में फंसा हुआ था। इसका सबसे बड़ा कारण भारत-पाकिस्तान के बीच हुआ सिंधु जल समझौता था।

अबू सलेम को सुप्रीम कोर्ट से झटका, समयपूर्व रिहाई की याचिका खारिज

1993 मुंबई सिलसिलेवार बम धमाकों के मामले में उम्रकैद की सजा काट रहा है गैंगस्टर
जेल में बिताई अवधि और रिमिशन को 25 साल की सीमा में जोड़ने की थी मांग

नई दिल्ली ।

सुप्रीम कोर्ट ने 1993 के मुंबई सिलसिलेवार बम धमाकों के मामले में उम्रकैद की सजा काट रहे गैंगस्टर अबू सलेम को बड़ा झटका दिया है। शीर्ष अदालत ने गुरुवार को सलेम की समयपूर्व रिहाई की मांग वाली याचिका खारिज कर दी। सलेम ने जेल में मिली रियायत (रिमिशन) और विचाराधीन कैदी के तौर पर बिताई गई अवधि को उसकी 25 साल की अधिकतम सजा की अवधि में शामिल करने की मांग की थी।जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की पीठ ने मामले में फैसला सुनाते हुए सलेम की याचिका खारिज कर दी। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में बॉम्बे हाईकोर्ट के फैसले को बरकरार रखा है। इससे पहले 27 जुलाई को शीर्ष अदालत ने सलेम की याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रखा था।

क्या थी अबू सलेम की दलील? अबू सलेम की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता ऋषि मल्होत्रा ने अदालत में दलील दी थी कि

मुकदमे के दौरान जेल में विचाराधीन कैदी के रूप में बिताई गई अवधि को उसकी सजा में समायोजित किया जाना चाहिए। वकील ने तर्क दिया कि टाडा अदालत भी सलेम के विचाराधीन कैदी के तौर पर बिताए समय को सजा की अवधि में समायोजित करने का निर्देश दे चुकी है। इसके अलावा, उन्होंने जेल में अच्छे आचरण के आधार पर अर्जित रिमिशन को भी वास्तविक कारावास की अवधि में शामिल करने की मांग की।

आजम खान पर एक और एफआईआर

नई दिल्ली।

समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान के खिलाफ एक और एफआईआर दर्ज हुई है। लखनऊ हज कमेटी की करीब 60 हजार वर्गफीट जमीन एक प्राइवेट बिल्डर को बेचने के मामले में विजिलेंस ने लखनऊ सेक्टर थाने में केस दर्ज किया है। आजम खान के साथ ही हज कमेटी के तत्कालीन सचिव लईक अहमद, डॉक्टर एमएए खान, अमीश डेवलपर्स के मालिक मोहम्मद अयूब और मुस्तकीम अहमद पर भी एफआईआर दर्ज हुई है।

आरोप है कि हज समिति के नियमों का उल्लंघन कर जमीन बेची गई, जिससे सरकार को 2 करोड़ 8 लाख रुपये से ज्यादा के राजस्व का नुकसान हुआ। यह एफआईआर उत्तर प्रदेश सतर्कता अधिष्ठान के लखनऊ सेक्टर थाने में दर्ज हुई है। शिकायत उत्तर प्रदेश सतर्कता अधिष्ठान लखनऊ के निरीक्षक ध्रुव चन्द्र मौर्य ने दर्ज कराई है।

हजार साल पुरानी हो सकती है उज्जैन के खड़े हनुमान जी की प्रतिमा

उज्जैन ।

बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन के खड़े हनुमान जी की प्रतिमा को लेकर महत्वपूर्ण खुलासा हुआ है, जिसमें पुरातत्व विभाग ने इसके करीब एक हजार साल पुरानी होने की संभावना जाहिर की है। इस प्राचीन प्रतिमा की उम्र और ऐतिहासिक पृष्ठभूमि का पता लगाने के लिए अब विशेषज्ञ और इतिहासकार गहन पड़ताल करने वाले है। यह चर्चा तब शुरू हुई जब सिंहस्थ 2028 की तैयारियों के तहत शहर के कंठाल चौराहे से छत्री चौक तक चल रहे सड़क चौड़ीकरण के दौरान मंदिर का भवन सड़क की जद में आया। मंदिर के निर्माण हिस्से को हटाने के बाद प्रतिमा को विस्थापित करने में आ रही कठिनाइयों ने एक संवेदनशील मुद्दा बना दिया। लोगों और दूर-दराज, यहां तक कि गुजरात, महाराष्ट्र और राजस्थान से भी श्रद्धालु, इस मूर्ति को एक चमत्कार मानकर दर्शनों के लिए पहुंचने लगे हैं।

सोशल मीडिया पर भी इस प्रतिमा से जुड़े वीडियो लगातार ट्रेंड कर रहे हैं। प्रतिमा की संभावित प्राचीनता को लेकर बढ़ती उत्सुकता के बीच, पुरातत्व विभाग ने शुरुआती आकलन में इसके करीब एक हजार वर्ष पुराना होने का अनुमान लगाया है। हालांकि, यह अभी अंतिम निष्कर्ष नहीं है और प्रमाणित करने के लिए गहन विशेषज्ञ अध्ययन की आवश्यकता है। अब इतिहासकार प्रतिमा की शिल्प शैली, उसकी मुद्रा, चेहरे की बनावट, शरीर की संरचना, आभूषण और निर्माण शैली का विश्लेषण करने वाले हैं।

सागर शराब त्रासदी पर खड़गे का वार...जवाबदेही से भाग रही डबल इंजन सरकार

नई दिल्ली ।

मध्य प्रदेश के सागर जिले में जहरीली शराब त्रासदी को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष और राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने भाजपा सरकार पर हमला बोला है।

उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा ने राज्य में भ्रष्टाचार की पराकाष्ठा लांघ दी है और लापरवाही के चलते अब लोगों की जान की कोई कीमत नहीं रही।

कांग्रेस नेता खड़गे ने जानकारी दी कि सागर में जहरीली शराब पीने से 31 लोगों की दुखद मौत हो चुकी है, जबकि 11 अन्य अब भी जिंदगी और मौत से जूझ रहे हैं। उन्होंने इन 31 परिवारों के उजड़ने पर दुख व्यक्त कर कहा कि किसी ने अपना बेटा, किसी ने पिता, किसी ने पति खोया है, लेकिन भाजपा सरकार के लिए यह महज एक और हादसा है। कांग्रेस अध्यक्ष ने दावा किया कि पिछले 22 सालों से भाजपा का यही तरीका रहा है। उन्होंने मोहन सरकार की घेराबंदी कर कई अन्य घटनाओं का भी जिक्र किया, जिसमें बालाघाट में 27 से अधिक बच्चों की मौत, इंदौर में दूषित पानी से 36 लोगों की जान जाना और जहरीली कफ सिरप से 25 बच्चों की मौत शामिल है। कांग्रेस नेता खड़गे ने बताया कि सीधी में एक साल के भीतर 53 प्रसूताओं की मौत हो गई, जो मोहन सरकार की घोर लापरवाही दर्शाती है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि चाहे शराब में जहर हो, पानी में या दवा में, हर बार कीमत मध्य प्रदेश की जनता अपनी जान देकर चुका रही है। उन्होंने डबल इंजन सरकार पर जवाबदेही से दोगुनी रफ्तार से भागने का आरोप लगाया। खड़गे ने आरोप लगाया कि जब जनता न्याय मांगती है तो जवाब में वाटर कैनन और आंसू

गैस का इस्तेमाल किया जाता है, जबकि कोई जवाबदेही नहीं लेता और न ही किसी को सजा मिलती है।

अल नीनो के बढ़ते असर से भारत में स्वास्थ्य जोखिम बढ़ा, डेंगू-मलेरिया को लेकर चेतावनी

- विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भारत को अत्यधिक स्वास्थ्य जोखिम वाले देशों में रखा

- अगस्त से अक्टूबर के बीच कम बारिश और अधिक गर्मी का अनुमान

नई दिल्ली ।

दुनिया के कई हिस्सों के मौसम को प्रभावित करने वाला अल नीनो लगातार मजबूत हो रहा है। इसके बीच विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भारत को स्वास्थ्य के लिहाज से अत्यधिक जोखिम वाले देशों की सूची में शामिल किया है। संगठन के आकलन के अनुसार दक्षिण एशिया के अधिकांश हिस्सों में अगस्त से अक्टूबर के बीच सामान्य से कम बारिश और अधिक गर्मी पड़ सकती है।

विश्व स्वास्थ्य संगठन ने 5 सितंबर को जारी अपनी रिपोर्ट 'वैश्विक जन स्वास्थ्य स्थिति विश्लेषण-अल नीनो 2026' में यह आकलन किया है। यह चेतावनी ऐसे समय आई है, जब भारत के कई हिस्सों में मच्छरों से फैलने वाली बीमारियों के मामले बढ़ रहे हैं।

दिल्ली में डेंगू-मलेरिया के मामले बढ़े

दिल्ली में अगस्त के दौरान डेंगू के 90 मामले सामने आए, जो इस साल किसी एक महीने में दर्ज सबसे अधिक मामले हैं। 29 अगस्त तक राजधानी में डेंगू के कुल मामलों की संख्या 311 पहुंच गई थी।

नगर निगम के आंकड़ों के मुताबिक, मलेरिया के मामले भी जुलाई में 17 से बढ़कर अगस्त में 53 हो गए। इस साल अब तक दिल्ली में मलेरिया के 119 मामले दर्ज किए जा चुके हैं।

हालांकि, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भारत में डेंगू या मलेरिया के मौजूदा मामलों को सीधे तौर पर अल नीनो से नहीं जोड़ा है। संगठन के मुताबिक, अल नीनो स्वास्थ्य जोखिम बढ़ाने वाला एक कारक हो सकता है। इसका प्रभाव स्थानीय मौसम, लोगों की संवेदनशीलता और स्वास्थ्य व्यवस्था की क्षमता पर निर्भर करेगा।

बढ़ते तापमान से कई बीमारियों का खतरा

भारत में बढ़ता तापमान विश्व स्वास्थ्य संगठन की प्रमुख चिंताओं में शामिल है। अत्यधिक गर्मी से लू लगने, गर्मी से थकावट और हीटस्ट्रोक का खतरा बढ़ सकता है। इससे हृदय, फेफड़े, गुर्दे और चयापचय संबंधी बीमारियों से जूझ रहे लोगों की स्थिति गंभीर हो सकती है।

गर्मी का असर गर्भवती महिलाओं और नवजात शिशुओं पर भी पड़ सकता है। वहीं बारिश में बदलाव से खाद्य उत्पादन प्रभावित होने पर कुपोषण और खाद्य असुरक्षा का खतरा बढ़ सकता है।

सीमावर्ती क्षेत्रों पर भी नजर

भारत-नेपाल और भारत-भूटान सीमा से लगे क्षेत्रों को भी जोखिम

वाले इलाकों में शामिल किया गया है। मौसम संबंधी घटनाओं के कारण विस्थापन होने पर संक्रामक बीमारियों के सीमा पार फैलने का खतरा बढ़ सकता है।

अल नीनो के दौरान प्रशांत महासागर के मध्य और पूर्वी उष्णकटिबंधीय हिस्से का समुद्री पानी सामान्य से अधिक गर्म हो जाता है। इसका प्रभाव दुनिया के कई हिस्सों में बारिश और तापमान के स्वरूप पर पड़ सकता है।

Web site : www.krantisamay.com & epaper.krantisamay.com www.facebook.com/krantisamay1 www.twitter.com/krantisamay1

ब्रिक्स सम्मेलन से भारत का विश्व को शांति का संदेश

(लेखक- सौरभ वार्ष्णेय)

पूरा विश्व इस समय जिस दौर से गुजर रहा है, उसमें भारत के नई दिल्ली में होने वाला ब्रिक्स शिखर सम्मेलन केवल राष्ट्राध्यक्षों की एक कूटनीतिक बैठक भर नहीं है। यह सम्मेलन बदलती हुई विश्व व्यवस्था, बढ़ते भू-राजनीतिक तनाव, आर्थिक अस्थिरता, युद्धों, ऊर्जा संकट, आपूर्ति श्रृंखला की चुनौतियों और विकासशील देशों की बढ़ती आकांक्षाओं के बीच भारत की भूमिका को समझने का एक महत्वपूर्ण अवसर है। 12 और 13 सितंबर 2026 को नई दिल्ली के भारत मंडपम में होने वाले 18 वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी भारत कर रहा है। ज्ञात रहे कि वर्ष 2026 में भारत चौथी बार ब्रिक्स की अध्यक्षता कर रहा है और इस बार उसका केंद्रीय विषय है (बिल्डिंग फॉर रेसिलिएंस इनोवेशन कोऑपरेशन एंड सस्टेनेबिलिटी) अर्थात लचीलेपन, नवाचार, सहयोग और सतत विकास के लिए निर्माण। भारत ने अपनी अध्यक्षता को ह्यूमैनिटी फर्स्ट की सोच से जोड़ते हुए ब्रिक्स को अधिक व्यावहारिक और विकासोन्मुख मंच बनाने पर जोर दिया है। यही इस सम्मेलन से भारत का पहला और सबसे बड़ा संदेश है—विश्व राजनीति को टकराव से निकालकर सहयोग की दिशा में ले जाने की आवश्यकता है। आज विश्व के अनेक हिस्से संघर्ष की आग में झुलस रहे हैं।

यूक्रेन संकट, पश्चिम एशिया की अस्थिरता और अमेरिका-चीन प्रतिद्वंद्विता ने अंतरराष्ट्रीय संबंधों को जटिल बना दिया है। ऐसे समय में भारत लगातार इस बात पर जोर देता आया है कि युद्ध किसी समस्या का स्थायी समाधान नहीं हो सकता। ब्रिक्स का मंच भारत को यह संदेश देने का अवसर देता है कि अलग-अलग राजनीतिक व्यवस्थाओं और राष्ट्रीय हितों वाले देश भी संवाद और सहयोग के माध्यम से साझा समस्याओं पर काम कर सकते हैं। भारत की विदेश नीति का मूल स्वर न तो किसी एक शक्ति-गुट के साथ खड़ा होना है और न किसी दूसरे गुट के विरोध में खड़ा होना। भारत अपने राष्ट्रीय हितों को सर्वोच्च रखते हुए सभी प्रमुख शक्तियों के साथ संवाद बनाए रखना चाहता है। यही रणनीतिक स्वायत्तता आज भारत की सबसे बड़ी कूटनीतिक ताकत बनती दिखाई दे रही है।

ब्रिक्स अब केवल पांच देशों का आर्थिक समूह नहीं रह गया है। इसके विस्तार ने इसे विकासशील और उभरती अर्थव्यवस्थाओं के लिए एक महत्वपूर्ण मंच बना दिया है। भारत इस मंच के माध्यम से ग्लोबल साउथ की उस आवाज को मजबूती देना चाहता है, जो लंबे समय से वैश्विक संस्थाओं में अधिक प्रतिनिधित्व की मांग करती रही है।

संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक जैसी संस्थाओं की निर्णय प्रक्रिया में विकासशील देशों की वास्तविक आर्थिक और जनसंख्या-आधारित ताकत के अनुरूप प्रतिनिधित्व का सवाल लगातार उठता रहा है।

भारत का संदेश स्पष्ट है—21वीं सदी की वैश्विक व्यवस्था 20वीं सदी की शक्ति-संरचना के आधार पर नहीं चल सकती। विश्व अर्थव्यवस्था में उभरती अर्थव्यवस्थाओं की भूमिका लगातार बढ़ रही है। इसलिए वैश्विक संस्थाओं में भी उनकी आवाज और भागीदारी बढनी चाहिए।

नई दिल्ली में ब्रिक्स सम्मेलन का एक महत्वपूर्ण आयाम आर्थिक सहयोग भी होगा। भारत ब्रिक्स देशों के बीच व्यापार, निवेश, वित्तीय सहयोग, डिजिटल अर्थव्यवस्था, ऊर्जा सुरक्षा और आपूर्ति श्रृंखलाओं को अधिक मजबूत बनाने की दिशा में आगे बढना चाहता है। भारत की अध्यक्षता में व्यापार मंत्रियों की बैठकों में भी वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं को अधिक लचीला और विविध बनाने तथा छोटे एवं मध्यम उद्यमों को वैश्विक बाजार से जोडने पर जोर दिया गया है।भारत का अनुभव बताता है कि डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना, विशेषकर डिजिटल भुगतान, वित्तीय समावेशन और तकनीक आधारित सेवाएं विकासशील देशों के लिए परिवर्तनकारी साबित हो सकती हैं।

इसलिए ब्रिक्स के मंच से भारत का एक महत्वपूर्ण संदेश यह भी है कि तकनीक केवल विकसित देशों का विशेषाधिकार नहीं होनी चाहिए। भारत आज दुनिया के सामने अपनी डिजिटल क्षमता का उदाहरण प्रस्तुत कर सकता है। डिजिटल भुगतान को आम नागरिक तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। यदि ब्रिक्स देश डिजिटल भुगतान, फिनटेक, साइबर सुरक्षा और डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाते हैं, तो इससे विकासशील देशों के करोड़ों लोगों को लाभ मिल सकता है। यह भारत की उस सोच से मेल खाता है जिसमें तकनीक का उद्देश्य केवल आर्थिक लाभ नहीं, बल्कि आम आदमी का सशक्तीकरण भी है।

नई दिल्ली ब्रिक्स सम्मेलन का एक अत्यंत महत्वपूर्ण पक्ष भारत-चीन संबंध भी है। चीन की भागीदारी इस सम्मेलन को रणनीतिक रूप से और अधिक महत्वपूर्ण बनाती है। दोनों देशों के बीच सीमा विवाद और रणनीतिक अविश्वास के बावजूद हाल के वर्षों में संवाद की प्रक्रिया आगे बढ़ी है। भारत के सामने चुनौती यह है कि वह चीन के साथ संवाद बनाए रखते हुए अपने राष्ट्रीय हितों और सुरक्षा चिंताओं से समझौता न करे।

यही भारतीय कूटनीति की परीक्षा है—प्रतिस्पर्धा के बीच सहयोग और मतभेदों के बीच संवाद। भारत यह संदेश देना चाहता है कि किसी देश के साथ आर्थिक या राजनीतिक मतभेद होने का अर्थ यह नहीं कि संवाद के सभी रास्ते बंद कर दिए जाएं।

ब्रिक्स में रूस की महत्वपूर्ण भूमिका है। वहीं भारत के अमेरिका, यूरोप, जापान और ऑस्ट्रेलिया के साथ भी रणनीतिक संबंध मजबूत हुए हैं। भारत की यही बहुस्तरीय कूटनीति उसे अन्य देशों से अलग करती है। नई दिल्ली किसी एक ध्रुव की राजनीति का हिस्सा बनने के बजाय अनेक शक्तियों के साथ अपने संबंधों को संतुलित करना चाहती है।

यह संदेश भी महत्वपूर्ण है कि भारत की विदेश नीति किसी दूसरे देश की विदेश नीति की छाया नहीं है। भारत अपने हितों के आधार पर अमेरिका के साथ भी संबंध रख सकता है, रूस के साथ भी और चीन के साथ भी संवाद कर सकता है।विश्व में युद्ध और भू-राजनीतिक तनाव बढने का सीधा प्रभाव ऊर्जा और खाद्य सुरक्षा पर पड़ता है। तेल, गैस, उर्वरक, अनाज और आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति प्रभावित होने पर सबसे ज्यादा नुकसान विकासशील देशों को होता है। ब्रिक्स के मंच से भारत ऊर्जा और खाद्य सुरक्षा को सामूहिक वैश्विक जिम्मेदारी के रूप में प्रस्तुत कर सकता है। सम्मेलन के प्रमुख मुद्दों में खाद्य और ऊर्जा सुरक्षा, सार्वजनिक स्वास्थ्य, आपदा-रोधी क्षमता तथा आपूर्ति श्रृंखलाओं को मजबूत करना शामिल है।भारत का संदेश होना चाहिए कि विकासशील देशों की अर्थव्यवस्थाओं को भू-राजनीतिक संघर्षों का अनावश्यक शिकार नहीं बनाया जाना चाहिए।

जलवायु परिवर्तन आज पूरी मानवता के सामने चुनौती है। बाढ़, सूखा, अत्यधिक गर्मी, समुद्री स्तर में वृद्धि और बदलते मौसम का प्रभाव गरीब और विकासशील देशों पर अधिक पड़ता है।भारत की अध्यक्षता में सतत विकास और लचीली अर्थव्यवस्था पर जोर इस दृष्टि से महत्वपूर्ण है।भारत का संदेश यह होना चाहिए कि पर्यावरण संरक्षण के नाम पर विकासशील देशों के विकास के अधिकार को सीमित नहीं किया जा सकता। विकसित देशों को वित्त, तकनीक और क्षमता निर्माण में विकासशील देशों की मदद करनी चाहिए।भारत लंबे समय से आतंकवाद के खिलाफ कठोर और साझा वैश्विक कार्रवाई की वकालत करता रहा है। आतंकवाद किसी एक देश की समस्या नहीं है। इसका नेटवर्क सीमाओं से परे काम करता है और आधुनिक तकनीक तथा डिजिटल माध्यमों का इस्तेमाल करता है।ब्रिक्स देशों के बीच आतंकवाद, संगठित अपराध, साइबर अपराध और आर्थिक अपराधों से मुकाबले में सहयोग बढ़ाना समय की जरूरत है। भारत आर्थिक अपराधियों और सीमा पार वित्तीय गतिविधियों के खिलाफ बेहतर अंतरराष्ट्रीय सहयोग की दिशा में भी पहल कर रहा है।नई दिल्ली में दुनिया के प्रमुख उभरते देशों के नेताओं का जुटना अपने आप में भारत की बढ़ती वैश्विक प्रतिष्ठा का प्रमाण है।भारत ने अपनी अध्यक्षता के दौरान देश के 25 से अधिक शहरों में 350 से ज्यादा बैठकें और उच्चस्तरीय कार्यक्रम आयोजित किए हैं। इससे यह संकेत मिलता है कि भारत ब्रिक्स को केवल राजधानी-केंद्रित कूटनीतिक मंच के बजाय व्यापक जनभागीदारी और विकास के मंच के रूप में देख रहा है।यह भारत की एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य वाली व्यापक सोच के साथ भी जुड़ता है।

असली सफलता घोषणाओं में नहीं, परिणामों में हालांकि किसी भी अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन की सफलता केवल संयुक्त घोषणा या बड़े-बड़े वक्तव्यों से नहीं मापी जा सकती।नई दिल्ली में आयोजित होने वाला ब्रिक्स सम्मेलन भारत की विदेश नीति के उस संतुलित स्वरूप को दुनिया के सामने रखने का अवसर है जिसमें राष्ट्रीय हित, वैश्विक सहयोग और रणनीतिक स्वायत्तता तीनों साथ चलते हैं। भारत दुनिया को यह संदेश दे सकता है कि नई वैश्विक व्यवस्था किसी एक देश के प्रभुत्व पर आधारित नहीं होनी चाहिए। इसमें सभी क्षेत्रों, सभी सभ्यताओं और सभी विकास स्तर वाले देशों की भागीदारी होनी चाहिए।

भारत यह भी स्पष्ट कर सकता है कि ब्रिक्स किसी देश या पश्चिमी दुनिया के खिलाफ गठबंधन नहीं, बल्कि वैश्विक आर्थिक और राजनीतिक व्यवस्था को अधिक प्रतिनिधित्वपूर्ण बनाने का मंच है। यही दृष्टिकोण भारत को एक पुल की भूमिका देता है—पूर्व और पश्चिम के बीच, विकसित और विकासशील देशों के बीच तथा प्रतिस्पर्धा और सहयोग के बीच।नई दिल्ली से दुनिया को यदि कोई सबसे महत्वपूर्ण संदेश जाना चाहिए तो वह यही है।

संपादकीय

एआई का स्याह सच

एआई के सूत्रधार रहे शोधकर्ता लगातार धारदार होती एआई को लेकर जो गंभीर चिंता जता रहे हैं, उसमें मानव सभ्यता के लिए आसन्न संकट की आहट सुनायी देती है। पहले भी दबी-खुली जुबान में एआई के संस्थापक सूत्रधार ऐसी चिंता गाहे-बगाहे जाहिर कर चुके हैं। इसी कड़ी में अब एन्थ्रोपिक के रिसर्चर जैकब कॉक्सन के इस्तीफे और उनकी इस बात पर व्यक्त की गई गंभीर चिंताओं ने इस बहस को और तेज कर दिया है। जब कोई ऐसा व्यक्ति जो एन्थ्रोपिक व ओपन एआई जैसे महत्वपूर्ण संस्थानों में अहम भूमिका निभा चुका हो, यह दावा करता है कि एआई की बड़ी कंपनियां इंसानी जिंदगी के साथ जुआ खेल रही हैं, तो मामला गंभीर हो जाता है। ऐसे में सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न यही उठता है कि एआई से जुड़े शोध-अनुसंधान के कार्य को क्या जिम्मेदारी से आगे बढ़ाया जा रहा है? दरअसल, कॉक्सन की असली चिंता खुद को बेहतर बनाने वाली सुपरइंटेलिजेंस की तरफ बढ़ती अंधी होड़ है। जिसके बारे में आशंका जतायी जा रही है कि ऐसा सिस्टम तैयार किया जा रहा है जो आगे चलकर कई क्षेत्रों में इंसानी क्षमताओं से भी आगे निकल सकता है। सबसे बड़ी चिंता की बात यह है कि डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर,संसाधनों और संस्थानों को शिकार बनाने की क्षमता भी हासिल कर सकता है। इससे भी अधिक चिंता की बात यह है कि एन्थ्रोपिक के अपने अलाइनमेंट साइंस प्रमुख, इवान हुबिंगर ने भी माना है कि कंपनी के पास अभी तक सुपरइंटेलिजेंट सिस्टम को इंसानी हितों के अनुकूल बनाने का कोई समाधान मौजूद नहीं है। निश्चित रूप से ऐसी बातें एआई उद्योग के मूल में विद्यमान खतरनाक विरोधाभास को ही उजागर करती हैं। कंपनियां तेजी से यह मानकर चल रही हैं कि एडवांस्ड एआई से बहुत बड़े जोखिम मानवता के समक्ष उत्पन्न हो सकते हैं। लेकिन इस हकीकत को जानते-बूझते हुए भी इस क्षेत्र में जारी मारक स्पर्धा उन्हें ज्यादा सक्षम सिस्टम बनाने को बाध्य कर रही है। दरअसल, एआई के क्षेत्र में जारी विश्वव्यापी प्रतिस्पर्धा उन्हें लगातार उन्नत सिस्टम बनाने को मजबूर कर रही है। उनकी आशंका है कि यदि वे ऐसा नहीं करते हैं तो दूसरी कंपनी ऐसी पहल करके विश्व के एआई बाजार पर वर्चस्व बना लेगी। निश्चित रूप से यह अंधी होड़ एक दिन मानवता को एक भयावह तबाही के दरवाजे पर खड़ा कर सकती है। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि आज दुनिया में एआई के प्रयोग से चिकित्सा, विज्ञान और उत्पादन के क्षेत्र में आशातीत लाभ मिले हैं। लेकिन इसके बावजूद तकनीकी प्रगति को सिर्फ इस आधार पर नहीं मापा जा सकता है कि उससे क्षमताएं कितनी बेहतर स्थिति में आ पहुंची हैं। एआई के क्षेत्र में की जा रही तरक्की के साथ सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इसके साथ ही सुरक्षा और जवाबदेही भी उसी रफ्तार से आगे बढ़नी चाहिए। सही मायने में लगातार शोध-अनुसंधान के जरिये बड़े पैमाने पर उन्नत एआई क्षमताएं हासिल करने के गंभीर आक्षेप चिंता की बात है। यदि अमेरिका और चीन के बीच जारी गला-काट स्पर्धा शक्तिशाली एआई के विस्तार को तेज कर रही है और वहीं दूसरी ओर कंपनियां अपने सिस्टम को सुरक्षित रखने के लिये संघर्ष कर रही हैं तो इसके जोखिम कॉरपोरेट प्रतिस्पर्धा से कहीं अधिक बढ़ जाते हैं। निश्चित रूप से ऐसी स्थिति में सरकारें इंसानियत के भविष्य से जुड़े फैसले टेक कंपनियों के भरोसे नहीं छोड़ सकती हैं। बड़ी एआई लैब्स के लिये लागू करने योग्य सुरक्षा मानक, स्वतंत्र निगरानी व जोखिम का पारदर्शी आकलन करना जरूरी है।

पर्युषण : मन की भटकन मिटाकर आत्मा को निर्मल बनाने वाला अलौकिक पर्व

(लेखक- कांतिलाल मांडोत)

(पर्युषण महापर्व तीसरा दिन)

जैन धर्म में पर्युषण महापर्व का स्थान अत्यंत ऊंचा और विशिष्ट है। यह केवल धार्मिक परंपरा निभाने का अवसर नहीं, बल्कि मनुष्य को अपने भीतर झांकने, जीवन का मूल्यांकन करने और आत्मा को विकारों से मुक्त करने की प्रेरणा देने वाला पर्व है। जैन दर्शन का मूल संदेश अहिंसा, संयम, अपरिग्रह, सत्य, करुणा और आत्मजागरण है। पर्युषण इन्हीं सिद्धांतों को जीवन में उतारने का विशेष अवसर प्रदान करता है। यही कारण है कि इसे पर्वराज कहा गया है। यह बाहरी उत्सव से अधिक अंतरात्मा का उत्सव है, जिसमें श्रावक-श्राविकाएं अपने जीवन को धर्म, तप, त्याग और आत्मचिंतन से समृद्ध करने का प्रयास करते हैं।

वर्षा ऋतु प्रकृति को नई ऊर्जा देती है। गर्मी से सूखी धरती वर्षा का जल पाकर फिर हरी-भरी हो जाती है। इसी प्रकार चातुर्मास में संतों और साध्वियों के सान्निध्य से समाज के भीतर भी धर्म की चेतना का संचार होता है। उनकी वाणी मनुष्य को संसार की भागदौड़ से कुछ समय हटकर आत्मा की ओर देखने की प्रेरणा देती है। चातुर्मास के दौरान धर्मसभा, स्वाध्याय, सामायिक, प्रतिक्रमण, तप, जाप और संयम जैसी साधनाओं के माध्यम से श्रावक-श्राविकाओं को आत्मिक विकास का अवसर मिलता है। इसी धार्मिक वातावरण में पर्युषण का आगमन मनुष्य के लिए विशेष जागरण का संदेश लेकर होता है।

जैन धर्म में भगवान महावीर ने मनुष्य को बाहरी उपलब्धियों से अधिक अपने स्वभाव की पहचान करने का मार्ग बताया। मनुष्य जब अपने वास्तविक स्वरूप को भूलकर परभाव और विषय-वासनाओं में उलझ जाता है, तब उसके जीवन में अशांति बढ़ती जाती है। इच्छा, क्रोध, मान, माया और लोभ मन को निरंतर भटकाते रहते हैं। पर्युषण इस भटकन को रोककर व्यक्ति को अपने भीतर लौटने का अवसर देता है। यह पर्व पूछता है कि हम वर्षभर किस दिशा में चलते रहे, हमारे व्यवहार से किसी को दुख तो नहीं पहुंचा, हमने अपने जीवन में कितना संयम अपनाया और आत्मकल्याण के लिए कितना पुरुषार्थ किया।

आज का जीवन सुविधाओं से भरपूर होने के बावजूद मानसिक तनाव और असंतोष से घिरा दिखाई देता है। मनुष्य बाहरी सुखों की खोज में लगातार दौड़ रहा है, लेकिन भीतर की शांति उससे दूर होती जा रही है। जैन धर्म का अध्यात्म इसी समस्या का समाधान प्रस्तुत करता है। वह बताता है कि स्थायी आनंद बाहरी वस्तुओं में नहीं, बल्कि आत्मिक शुद्धि में है। पर्युषण इसी सत्य को अनुभव करने का अवसर है। इन दिनों श्रावक-श्राविकाएं अपनी दिनचर्या में धर्म को प्रमुखता देते हैं और भोजन, मनोरंजन तथा सांसारिक व्यस्तताओं के स्थान पर आत्मचिंतन और साधना को महत्व देते हैं।

पर्युषण का एक बड़ा उद्देश्य तप और त्याग की भावना को मजबूत करना है। अपनी क्षमता के अनुसार उपवास, एकासन, आयंबिल, सामायिक, स्वाध्याय और अन्य धार्मिक नियमों का पालन करने से व्यक्ति में आत्मअनुशासन विकसित होता है। तप केवल शरीर को कष्ट देने का साधन नहीं है, बल्कि इच्छाओं पर नियंत्रण और मन को साधने की प्रक्रिया है। जब व्यक्ति अपनी आदतों और इच्छाओं पर संयम करना सीखता है, तब उसके भीतर धैर्य और आत्मविश्वास बढ़ता है। इससे जीवन के अन्य क्षेत्रों में भी अनुशासन और संतुलन आता है।

पर्युषण श्रावक-श्राविकाओं को क्षमा, करुणा और मैत्री का संदेश भी देता है। मन में किसी के प्रति नाराजगी, द्वेष या कटुता बनी रहे तो आत्मा पर उसका प्रभाव पड़ता है। इसलिए यह पर्व पुराने मनमुटाव को समाप्त करने और संबंधों में मधुरता लाने का अवसर देता है। क्षमा मांगना और क्षमा करना दोनों ही आत्मिक शुद्धि के महत्वपूर्ण साधन हैं। इससे मन का बोझ हल्का होता है और व्यक्ति भीतर से अधिक शांत अनुभव करता है।

इस पर्व का सबसे महत्वपूर्ण पक्ष आत्मनिरीक्षण है। जिस प्रकार वर्षभर के व्यापार का हिसाब लगाया जाता है, उसी प्रकार पर्युषण में मनुष्य को अपने आचरण का लेखा-जोखा करना चाहिए। मैंने किसके साथ अन्याय किया, किसके मन को ठेस पहुंचाई, कहां क्रोध किया, कहां लोभ के कारण गलत निर्णय लिया और किन अवसरों पर अहंकार ने मुझे प्रभावित किया, इन प्रश्नों पर विचार करना ही सच्ची धर्मसाधना है। आत्मचिंतन से अपनी कमियों का पता चलता है और उन्हें सुधारने की दिशा मिलती है।

मन की भटकन को समझाने वाली गुड़ की राब और हलुए की कथा भी यही संदेश देती है कि मनुष्य कई बार अपनी सीमित आदतों को ही जीवन का सर्वोच्च सुख मान लेता है। जब उसे बेहतर अनुभव मिलता है तो उसकी सोच बदल जाती है। इसी प्रकार सांसारिक विषयों में उलझा मन क्षणिक सुख को ही वास्तविक आनंद समझता रहता है। धर्म, संयम और आत्मसाधना का अनुभव होने पर उसे समझ में आता है कि स्थायी शांति का मार्ग बाहर नहीं, भीतर है। पर्युषण इसी नई अनुभूति की ओर ले जाने वाला अवसर है।

जैन धर्म की महिमा इसी में है कि वह मनुष्य को केवल पूजा-पाठ तक सीमित नहीं रखता, बल्कि उसके आचरण में परिवर्तन लाने की प्रेरणा देता है। अहिंसा को जीवन का आधार बनाना, जीव मात्र के प्रति करुणा रखना, आवश्यकता से अधिक संग्रह से बचना, सत्य और संयम का पालन करना तथा आत्मा की शुद्धि के लिए निरंतर प्रयास करना जैन जीवनदर्शन की महान देन है। पर्युषण इन सिद्धांतों को व्यवहार में उतारने का विशेष अवसर प्रदान करता है।

इसलिए पर्युषण को केवल आठ दिनों का धार्मिक आयोजन मानना इसके वास्तविक महत्व को सीमित करना होगा। यह मनुष्य को स्वयं से मिलने का अवसर देता है। यह भटकते मन को विराम देता है, विकारों को पहचानने की शक्ति देता है और आत्मा की ओर लौटने का मार्ग दिखाता है। श्रावक-श्राविकाओं के लिए यह पर्व धर्मलाभ के साथ मानसिक शांति, आत्मसंयम, सद्भाव, क्षमा और जीवन में सकारात्मक परिवर्तन का माध्यम बन सकता है। यदि पर्युषण की साधना केवल मंदिर और धर्मसभा तक सीमित न रहकर दैनिक जीवन के व्यवहार में उतर जाए, तो यही इस अलौकिक पर्व की सबसे बड़ी सार्थकता होगी।

(रु103 जलवन्त टाउनशिप पूणा बॉम्बे मार्केट रोड, नियर नन्दालय हवेली सूरत मो 99749 40324 वरिष्ठ पत्रकार साहित्यकार स्तम्भकार)

सन्मार्ग की प्रवृत्ति

उत्तम कार्य की कार्य प्रणाली भी प्राय- उत्तम होती है। दूसरों की सेवा या सहायता करनी है, तो प्राय- मधुर भाषण, नम्रता, दान, उपहार आदि द्वारा उसे संतुष्ट किया जाता है। परन्तु कई बार इसके विपरीत क्रिया-प्रणाली ऐसी कठोर, तीक्ष्ण एवं कटु बनानी पड़ती है कि लोगों को भ्रम हो जाता है कि कहीं यह दुर्भाव से प्रेरित होकर तो नहीं किया गया। ऐसे अवसरों पर वास्तविकता का निर्णय करने में बहुत सावधानी बरतने पड़ती है। सीधे-सादे अवसरों पर सीधी-सादी प्रणाली से भली प्रकार काम चल जाता है। भूखे, प्यासे की सहायता करनी है, तो वह कार्य अन्न-जल देने के सीधे-सादे तरीके से चल जाता है। किसी दुःखी या अभावग्रस्त को अभीष्ट वस्तुएं देकर उसकी सेवा की जा सकती है। धर्मशाला, कुआं, पाठशाला, अनाथालय, औषधालय आदि द्वारा लोकसेवा की जा सकती है। ऐसे कार्य निश्चय ही श्रेष्ठ हैं और उनकी आवश्यकता व उपयोगिता सर्वत्र स्वीकारी जा सकती है। परन्तु कई बार ऐसी सेवा की भी बड़ी आवश्यकता होती है, जो प्रत्यक्ष में बुराई मालूम पड़ती है और उसे करने वाले को अपयश ओढ़ना पड़ता है। इस मार्ग को अपनाने का साहस हर किसी में नहीं होता।

दुष्ट और अज्ञानियों को उस मार्ग से छुड़ाना, जिस पर वे बड़ी ममता और अहंकार के साथ प्रवृत्त हो रहे हैं, साधारण काम नहीं है। सीधे आदमी की भूल ज्ञान से, तर्क से, समझाने से सुधर जाती है पर जिनकी मनोभूमि अज्ञानान्धकार से कलुषित हो, साथ ही जिनके पास कुछ शक्ति भी है, वे ऐसे मदान्ध हो जाते हैं कि सीधी-सादी क्रिया-प्रणाली का उन पर प्राय- कुछ असर नहीं होता। मनुष्य शरीर धारण करने पर भी जिनमें पशुत्व की प्रधानता है, दुनिया में उनकी कमी नहीं है। उन्हें ज्ञान, तर्क, नम्रता, सज्जनता, सहनशीलता से अनीति के दुःखदाई मार्ग से पीछे नहीं हटाया जा सकता। पशु केवल दो चीजें पहचानता है- एक लोभ, दूसरा भय। दाना, घास खिला उसे ललचा कर कहीं भी ले जाइए, वह पीछे-पीछे चलेगा या लाठी का डर दिखा जिधर चाहे उधर ले जा सकते हैं। भय या लोभ से अज्ञानियों को, कुमार्गगामियों को सन्मार्ग में प्रवृत्त किया जा सकता है। भय उत्पन्न करने के लिए दंड का आश्रय लिया जाता है। लोभ के लिए कोई ऐसा आकषर्ण उसके सामने उपस्थित करना पड़ता है जो आज की अपेक्षा अधिक सुखदायी हो। नशेबाजी, व्यभिचार आदि के दुष्परिणाम को बढ़ा-चढ़ाकर, बताकर कई बार उस ओर चलने वालों को इतना डरा दिया जाता है कि वे उसे स्वत- छोड़ देते हैं।

विचार मंथन

ब्रिक्स सम्मेलन में भारत की महत्वपूर्ण भूमिका

(लेखक- सनत जैन)

देश की राजधानी दिल्ली में 12 एवं 13 सितंबर को ब्रिक्स का सम्मेलन होने जा रहा है। दुनिया की आधी आबादी ब्रिक्स के सदस्य देशों में रहती है। 20 बरस पहले ब्रिक्स की नीव रखी गई थी। उस समय सदस्य देशों की संख्या 5 थी, जो अब बढ़कर 11 हो गई है। 20 वर्षों में दुनिया की राजनीति, अर्थव्यवस्था और आपसी संबंधों में वैश्विक स्तर पर बड़े-बड़े बदलाव देखने को मिल रहे हैं। ऐसी स्थिति में जब भारत ब्रिक्स देशों के संगठन की अध्यक्षता कर रहा है, तो ऐसे समय में भारत की भूमिका और भी महत्वपूर्ण हो जाती है। जिस तरह से दुनियाभर में व्यापार और नवाचार को लेकर नए-नए अवसर देखने को मिल रहे हैं। वैश्विक व्यापार संधि के बाद दुनिया के आर्थिक, सामरिक एवं सामाजिक रिश्तों के समीकरण भी बड़ी तेजी के साथ बदल रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय एवं अन्य संस्थाओं की भूमिका जिस तरह से घट रही है, ऐसी स्थिति में ब्रिक्स के देश अपने हितों का संवर्धन करना चाहते हैं। ऐसी स्थिति में सभी को सजगता के साथ विचार-विमर्श करते हुए दीर्घकालीन दृष्टि को ध्यान में रखते हुए निर्णय लेने होंगे। अध्यक्ष के रूप में भारत की भूमिका अति महत्वपूर्ण है।

भारत को अमेरिका, रूस, चीन ने निशाने पर ले रखा है। वर्तमान में यह तीनों महाशक्तियां हैं। पिछले कुछ वर्षों से अमेरिका के निशाने पर भारत है। इसी तरह से चीन भी भारत के साथ व्यापार और जमीनी विवाद को लेकर प्रतिस्पर्धा में शामिल है। वर्तमान संदर्भ में अमेरिका के कारण भारत और रूस के बीच पहले वाले संबंध नहीं रहे, जिसके कारण भारत अध्यक्ष होते हुए भी तीन पाटों के बीच में से अपने आपको कैसे सुरक्षित रख पाता है, इसकी सबसे बड़ी परीक्षा भारत को देनी है। ब्रिक्स देशों द्वारा न्यू डेवलपमेंट बैंक की स्थापना की गई है। इसमें सदस्य देशों के लिए परिवहन, स्वच्छ ऊर्जा, जलापूर्ति और पर्यावरण जैसे क्षेत्रों की 140 परियोजनाओं के लिए 46 अरब डॉलर का ऋण भी दिया जा चुका है। ब्रिक्स देश का आपसी व्यापार 1.3 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंच गया है। वर्तमान में अमेरिका डॉलर मुद्रा को लेकर जिस तरह का दबाव बनाता है, प्रतिबंधों के माध्यम से दुनिया के अन्य देशों के लिए परेशानी खड़ा करता है। इसको देखते हुए दुनिया के देश अब डॉलर मुद्रा से बाहर भी निकालना चाहते हैं। वैश्विक व्यापार के लिए नई मुद्रा व्यवस्था की स्वीकारता पर काम कर रहे हैं। अमेरिका पिछले 6 दशक से जिस तरह की दादागिरी करता आ रहा है, वही दादागिरी अभी भी करना चाहता है। ऐसी स्थिति में ब्रिक्स संगठन की भूमिका अति महत्वपूर्ण हो गई है।

पिछले एक दशक में चीन बड़ी तेजी के साथ आर्थिक एवं तकनीकी के क्षेत्र में आगे बढ़ा है। रुस एक महाशक्ति होते हुए भी यूक्रेन के साथ युद्ध में फंसा हुआ है। अमेरिका का दूसरी बार राष्ट्रपति बनने के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने जिस तरह से टैरिफ का खेल खेलकर अमेरिका के स्थान पर अपने स्वयं के लाभ के लिए राष्ट्रपति पद का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है, उसके कारण अमेरिका इन दोनों आर्थिक और सामरिक रूप से बहुत कमजोर हो गया है। रही सही कसर ईरान युद्ध ने पूरी कर दी है। भारत के ऊपर अमेरिका और चीन का बड़ा दबाव है। रूस के साथ भी भारत के संबंध हमेशा रहे हैं। रूस ने हमेशा भारत की मदद की है। ऐसी स्थिति में भारत किस चतुराई के साथ ब्रिक्स देशों की अध्यक्षता करते हुए कूटनीति और रिश्तो के माध्यम से भारत के हितों की रक्षा करते हुए आर्थिक एवं सामरिक हितों को बेहतर बना सकता है, यह भारत के लिए एक परीक्षा की घड़ी है। भारत ने ईरान, अमेरिका और इजरायल के युद्ध में अपने आप को अमेरिका और इजरायल के साथ जोड़कर रखा। यूक्रेन युद्ध में भी रूस के समर्थन और विपक्ष में शांत रहा। गाजा में इजरायली युद्ध में जब हजारों फिलिस्तीन नागरिकों की मौत हुई उस समय भी भारत ने चुप्पी साध ली। अमेरिका और ईरान के युद्ध के समय खुलकर अमेरिका का साथ दिया। जिसके कारण भारत की भूमिका को लेकर हर जगह प्रश्न चिन्ह लग रहा है।

ऐसी स्थिति में भारत को अपनी विदेश नीति में परिवर्तन करना होंगे। डरने की बजाय भारत के हितों को लेकर चीन और रूस के साथ बराबरी से बात करनी होगी। ब्रिक्स के सदस्य देशों के हितों का भी ध्यान रखना होगा। सही मायने में यह भी कहा जा सकता है, जिस तरह से पंचशील सिद्धांत के कारण भारत की विश्व स्तर पर एक अलग भूमिका थी, कुछ उसी तरह की विदेश नीति अपनाते हुए भारत एक महत्वपूर्ण भूमिका वर्तमान और भविष्य में अदा कर सकता है। भारत की सबसे ज्यादा युवा आबादी है। भारत की आबादी दुनिया के अन्य देशों के मुकाबले ज्यादा है। व्यापारिक एवं सामरिक दृष्टि से भारत को उपेक्षित कर पाना बड़ी से बड़ी महाशक्ति के लिए आसान नहीं है।

इस आत्मविश्वास के साथ भारत को इस मौके का लाभ उठाना होगा। सरकार को चाहिए, विदेश और अर्थनीति के विशेषज्ञों को भी, वह किसी भी पार्टी से जुड़े हों, वर्तमान में उनकी कोई भूमिका हो या ना हो, उन सभी के साथ संवाद करके इस अवसर का लाभ उठाना चाहिए।

Web site : www.krantisamay.com & epaper.krantisamay.com www.facebook.com/krantisamay1 www.twitter.com/krantisamay1

आईडीबीआइ बैंक के निजीकरण की दिशा में कदम, फेयरफैक्स डील में आगे

सरकार और फेयरफैक्स के बीच कीमत पर अटका मामला, शेयर 11 फीसदी गिरे

मुंबई ।

देश के प्रमुख सरकारी बैंक आईडीबीआई बैंक के निजीकरण की प्रक्रिया अब निर्णायक मोड़ पर पहुंच गई है। सरकार बैंक में अपनी 60.72 फीसदी हिस्सेदारी बेचने की तैयारी में है, और इस दौड़ में कनाडा की वित्तीय कंपनी फेयरफैक्स में सबसे आगे दिख रही है। यदि आपका भी खाता इस बैंक में है, तो यह खबर आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकती है। सूत्रों के मुताबिक फेयरफैक्स ने प्रति शेयर करीब 81 रुपये की पेशकश की है, जिससे सरकार की हिस्सेदारी का मूल्य लगभग 53,000 करोड़ रुपये हो जाता है। हालांकि, इस प्रस्तावित कीमत पर सरकार और फेयरफैक्स के बीच अंतिम सहमति अभी तक नहीं बन पाई है। इसी मुद्दे पर सोमवार को वित्त मंत्रालय में उच्च-स्तरीय बैठक भी हुई। इस खबर के सार्वजनिक होते ही बैंक के शेयरों में लगभग 11 फीसदी की बड़ी गिरावट दर्ज की गई। फेयरफैक्स का भारत में पहले से ही आईआईएफएल फाइनेंस और सीएसबी बैंक में निवेश है, जिसके कारण आईडीबीआई डील पूरी होने पर उसे भारतीय बैंकिंग नियमों के तहत कुछ निवेशों में बदलाव करना पड़ सकता है। बैंक के ग्राहकों के लिए राहत की बात यह है कि इस निजीकरण का उनके बैंकिंग परिचालन पर कोई सीधा असर नहीं पड़ेगा। बैंक पहले की तरह ही सुचारू रूप से काम करता रहेगा और मौजूदा सेवाएं एवं योजनाएं यथावत जारी रहेंगी।

सोना 182 रुपए सुस्त, चांदी 907 रुपए नरम

सोने का भाव 1,53,650 प्रति 10 ग्राम, चांदी 2,43,110 रुपए प्रति किलोग्राम

नई दिल्ली ।

कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों ने वैश्विक बाजारों में महंगाई की चिंता और ब्याज दरों में संभावित वृद्धि की उम्मीद बढ़ा दी है, जिसका असर सोने और चांदी पर साफ दिख रहा है। गुरुवार को दोनों कीमती धातुओं के कारोबार की शुरुआत सुस्ती के साथ हुई। घरेलू वायदा बाजार मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (एमसीएक्स) पर सोने और चांदी दोनों में गिरावट दर्ज की गई। खबर लिखे जाने तक, सोने का अक्टूबर वायदा 1,53,650 प्रति 10 ग्राम पर 113 की गिरावट के साथ कारोबार कर रहा था। यह 1,53,581 पर खुला था। इस साल सोने ने 1,80,779 के रिकॉर्ड उच्च स्तर को छुआ था। वहीं चांदी का दिसंबर वायदा भी दबाव में दिखा और यह 1,103 रुपए की गिरावट के साथ 2,43,110 रुपए प्रति किलोग्राम पर था। चांदी ने 2,43,292 रुपए पर कारोबार शुरू किया था। इस साल चांदी ने 4,20,048 रुपए प्रति किलोग्राम का सर्वोच्च स्तर बनाया है। अंतरराष्ट्रीय बाजार कॉमेक्स पर भी सोने और चांदी में सुस्ती देखने को मिली। सोना 4,458.90 डॉलर प्रति औंस पर 1.80 डॉलर की गिरावट के साथ कारोबार कर रहा था, जबकि यह 4,448 डॉलर पर खुला था। पिछले सत्र में सोना 4,460.70 डॉलर प्रति औंस पर बंद हुआ था। इस साल कॉमेक्स पर सोने का उच्चतम स्तर 5,586.20 डॉलर प्रति औंस रहा है। चांदी भी 0.57 डॉलर की गिरावट के साथ 68.07 डॉलर प्रति औंस पर कारोबार कर रही थी। चांदी 67.94 डॉलर प्रति औंस पर खुली थी, जबकि पिछला बंद भाव 68.64 था। अंतरराष्ट्रीय बाजार में चांदी ने इस साल 121.79 डॉलर प्रति औंस का सर्वोच्च स्तर छू लिया था। बढ़ती महंगाई और ब्याज दरों की आशंका के बीच निवेशकों की नजर अब केंद्रीय बैंकों की नीतियों पर टिकी है।

सैमसंग इंडिया में छंटनी, टीवी और होम अप्लायंसेज बिजनेस पर गिरी गाज

बढ़ती लागत और घटती मांग के चलते कंपनी ने उठाया कदम

नई दिल्ली । सैमसंग इंडिया ने अपने टेलीविजन और होम अप्लायंसेज बिजनेस में कर्मचारियों की छंटनी शुरू कर दी है। रिपोर्ट्स के अनुसार, कंपनी बढ़ती लागत, कम होती मांग और संगठनात्मक पुनर्गठन के बीच खर्चों में कटौती करने के लिए यह कदम उठा रही है। छंटनी का असर डायरेक्टर, टीम लीडर और मैनेजर सहित कई स्तरों के कर्मचारियों पर पड़ रहा है। सूत्रों के मुताबिक यह कटौती कई चरणों में की जा रही है और पिछले कुछ दिनों में कर्मचारियों को नौकरी से निकालने के लेटर जारी किए गए हैं। कुछ कर्मचारियों से तो नोटिस पीरियड पूरा किए बिना तुरंत कार्यमुक्त होने को कहा गया है। संपर्क करने पर, सैमसंग ने इस मामले पर टिप्पणी करने से इनकार कर दिया है। प्रभावित कर्मचारियों को तीन महीने की सैलरी और कंपनी में बिताए हर पूरे साल के लिए एक महीने की अतिरिक्त सैलरी का सेवरेंस पैकेज दिया जा रहा है। यह कदम ऐसे समय में उठाया गया है जब उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनियां कमजोर मांग और बढ़ती परिचालन लागत से जूझ रही हैं। मेमोरी चिप की ऊंची कीमतें, कच्चे माल की बढ़ती लागत और भारतीय रुपये के कमजोर होने से कंपनियों पर दबाव बढ़ा है।

एप्पल ने भारत में आईफोन लाइनअप की 40 फीसदी तक बढ़ाई कीमत

बढ़ोतरी के लिए मेमोरी की लागत, रुपए की कमजोरी को जिम्मेदार बताया

-नई दिल्ली।

एप्पल ने भारत में अपने आईफोन लाइनअप की कीमतों में 40 फीसदी की बढ़ोतरी की है। इसकी वजह मेमोरी की बढ़ती लागत है। वहीं, कंपनी ने अपने स्मार्टफोन की नई पीढ़ी लॉन्च करने के साथ आईफोन डुओ के साथ फोल्डेबल सेगमेंट में भी प्रवेश किया है, जिसकी कीमत 2.99 लाख रुपए तय की गई है। एप्पल ने आईफोन 17 के 256जीबी वेरिएंट की कीमत को 82,900 रुपए से बढ़ाकर 99,900 रुपए कर दी है, जो कीमत में 17,000 रुपए या 20.5 फीसदी की बढ़ोतरी है।

वहीं, 512जीबी वेरिएंट की कीमत 1,24,900 रुपए हो गई है, जो पहले 1,02,900 रुपए थी। इससे कीमत में 22,000 रुपए या 21.4 फीसदी की वृद्धि हुई है। आईफोन 18प्रो की शुरुआती कीमत 1,64,900 रुपए है, जो आईफोन 17प्रो की तुलना में 22 फीसदी ज्यादा है। वहीं, आईफोन 18प्रो मैक्स की शुरुआती कीमत 1,79,900 रुपए है, जो 20 फीसदी ज्यादा है। इसके अलावा, सबसे बड़ी बढ़ोतरी 1टीबी वाले आईफोन एयर की कीमत में हुई है। इसकी कीमत 40.6 फीसदी बढ़कर 2,24,900 रुपए हो गई है, जो पहले 1,59,900 रुपए थी। आईफोन एयर के 256जीबी और 512जीबी वेरिएंट भी 25 प्रतिशत महंगे हो गए हैं।

इसके अलावा, आईफोन 17ई की शुरुआती कीमत अब 79,900 रुपए है, जो 23.1 फीसदी ज्यादा हो गए हैं। वहीं, 128जीबी वाले आईफोन 16 की कीमत 28.6 फीसदी बढ़कर 89,900 रुपए हो गई है। भारत में एप्पल के प्रो मॉडल्स की कीमतों में हुई बढ़ोतरी कई प्रमुख बाजारों की तुलना में काफी ज्यादा है। अमेरिका में आईफोन 18प्रो और प्रो मैक्स की कीमतों में क्रमशः 9 फीसदी और 8 फीसदी की बढ़ोतरी हुई है। काउंटरपॉइंट रिसर्च के रिसर्च डायरेक्टर के मुताबिक भारत में आईफोन की कीमतें 20-30 फीसदी बढ़ी हैं, जो 8-10 फीसदी के वैश्विक औसत से काफी ज्यादा है।

उन्होंने कीमतों में इस बढ़ोतरी के लिए मेमोरी की लागत, रुपए की कमजोरी और घरेलू उत्पादन की बढ़ी हुई लागत को जिम्मेदार बताया है।

उन्होंने कहा कि आईफोन डुओ पर 20 फीसदी तक का आयात शुल्क लग सकता है, क्योंकि इसका स्थानीय स्तर पर असेंबल नहीं किया जाता है। साइबर मीडिया रिसर्च के इंडस्ट्री इंटेलिजेंस ग्रुप के प्रमुख ने कहा कि 2,99,900 रुपए की कीमत वाला आईफोन डुओ प्रो सीरीज से ऊपर एक अल्ट्रा-प्रीमियम श्रेणी स्थापित करता है।

उनके मुताबिक निकट अवधि में यह बड़े पैमाने पर बिक्री बढ़ाने वाले उत्पाद के बजाय मुख्य रूप से ब्रांड की प्रतिष्ठा बढ़ाने वाले उत्पाद के रूप में काम कर सकता है।

उन्होंने कहा कि फाइनेंसिंग विकल्प प्रो मैक्स यूजर्स को आकर्षित करने में मदद कर सकते हैं, जबकि निकट अवधि में आईफोन डुओ की शिपमेंट सीमित और सप्लाई की कमी से प्रभावित रहने की संभावना है। उन्होंने कहा कि फिलहाल फोल्डेबल स्मार्टफोन कुल स्मार्टफोन शिपमेंट का 1 फीसदी से भी कम हैं, लेकिन एप्पल के इस सेगमेंट में प्रवेश से इसके विकास को गति मिल सकती है।

जियो पेमेंट सॉल्यूशंस ने सीमा पार भुगतान सुविधा शुरू की

आरबीआई की मंजूरी के बाद जियो पेमेंट सॉल्यूशंस ने शुरू की पहल

नई दिल्ली ।

जियो फाइनेंशियल सर्विसेज की पूर्ण स्वामित्व वाली अनुषंगी जियो पेमेंट सॉल्यूशंस लिमिटेड (जेपीएसएल) ने भारतीय निर्यातकों को वैश्विक ग्राहकों से अंतरराष्ट्रीय भुगतान प्राप्त करने में मदद करने के लिए एक सीमा पार भुगतान मंच शुरू करने की बुधवार को घोषणा की। यह सुविधा भारतीय व्यवसायों की वैश्विक प्रतिस्पर्धी क्षमता को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। जेपीएसएल का यह नया मंच भारतीय निर्यातकों को वर्चुअल खातों, अंतरराष्ट्रीय कार्ड और स्थानीय भुगतान माध्यमों का उपयोग कर विदेशी ग्राहकों से भुगतान प्राप्त करने में सक्षम बनाएगा। भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) से पेमेंट एग्रीगेटर फॉर क्रॉस बॉर्डर (पीए-सीबी) के रूप में काम करने की मंजूरी मिलने के बाद यह पहल शुरू की गई है, जो निर्यात और भविष्य में आयात दोनों लेनदेन को कवर करेगी। जेपीएसएल ने बताया कि ऑनलाइन विक्रेता, डिजिटल कारोबारी और स्वतंत्र पेशेवर जैसे कई भारतीय व्यवसाय वैश्विक स्तर पर विस्तार कर रहे हैं, लेकिन अंतरराष्ट्रीय भुगतान प्राप्त करने की प्रक्रिया अक्सर जटिल और बिखरी हुई होती है।

इसमें कई भागीदार, अलग-अलग मुद्राएँ और अधिक कागजी कार्रवाई शामिल होती है। कंपनी के अनुसार, यह नया मंच इन जटिलताओं को दूर करेगा, वैश्विक भुगतान प्राप्त करने की प्रक्रिया को आसान बनाएगा, नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करेगा और कारोबारियों को उनके वैश्विक ग्राहकों को स्थानीय भुगतान विकल्प प्रदान करने में मदद करेगा।

अफ्रीका में चीनी ई-वाहन क्रांति- आयात बढ़ा, क्षेत्रीय अंतर स्पष्ट

- पूर्वी व मध्य अफ्रीका में स्थानीय असेंबली व वाणिज्यिक वाहनों पर जोर

नैरोबी ।

2026 की पहली छमाही में अफ्रीका में चीन से इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल और तिपहिया वाहनों के आयात में भारी वृद्धि दर्ज की गई है। यह महाद्वीप में इलेक्ट्रिक वाहनों (ईवी) को अपनाने की प्रक्रिया में मौजूद गहरे क्षेत्रीय अंतर को उजागर करता है, जो ईंधन खपत और वायु प्रदूषण घटाने के लिए महत्वपूर्ण है। उत्तरी अफ्रीकी देशों (मोरक्को, मिस्र, अल्जीरिया) की अगुवाई में चीन से दोपहिया और तिपहिया वाहनों का आयात 60त्न बढ़कर 11.46 करोड़ अमेरिकी डॉलर हो गया। यह क्षेत्र तैयार चीनी इलेक्ट्रिक स्कूटरों का प्रमुख बाजार बन गया है, जिन्हें उपभोक्ता आवागमन हेतु खरीदते हैं। मोरक्को ने सर्वाधिक 2.17 करोड़ अमेरिकी डॉलर की 80,188 इकाइयों का आयात किया। इसके विपरीत पूर्वी एवं मध्य अफ्रीका में ईवी स्टार्टअप कंपनियों में निवेश केंद्रित है, जो स्थानीय असेंबली, बैटरी स्वैपिंग नेटवर्क और वाणिज्यिक मोटरसाइकिल परिवेश तैयार कर रही हैं। विशेषज्ञ पीटर कोसाकोव्स्की के अनुसार, इस क्षेत्र में मोटरसाइकिलें मुख्यतः व्यावसायिक वाहनों के रूप में उपयोग होती हैं, जो यात्रियों व सामान को ढोती हैं। स्पाइरो जैसी कंपनियों ने बड़ा निवेश जुटाया है, लेकिन यहां उद्योग अभी भी आयातित कलपुर्जों की असेंबली पर निर्भर है; मोटर, नियंत्रक और बैटरी सेल जैसे प्रमुख घटक अब भी बाहर से आते हैं। उप-सहारा अफ्रीका में, दक्षिण अफ्रीका ने 69 लाख डॉलर की 19,635 इलेक्ट्रिक बाइक आयात की।

शेयर बाजार बढ़त पर बंद

सेंसेक्स 138, निफ्टी 46 अंक उछला

मुंबई ।

भारतीय शेयर बाजार गुरुवार को बढ़त पर बंद हुआ। बाजार में तीन कारोबारी सत्र के बाद आई ये तेजी दुनिया भर से मिले सकारात्मक संकेतों के साथ ही खरीददारी हावी होने से आई है। इसी के साथ ही पिछले तीन कारोबारी सत्र से जारी गिरावट पर भी ब्रेक लग गया। इसी कारण दिन भर के कारोबार के बाद 30 शेयरों पर आधारित बीएसई सेंसेक्स 138.36 अंक बढ़कर 74,902.59 पर बंद हुआ, जबकि 50 शेयरों वाला एनएसई निफ्टी 46 अंक बढ़कर 23,477.80 पर बंद हुआ।

आज बाजार में मिली-जुली धारणा लिए रहा, जहां लगभग 1,802 शेयरों में तेजी देखी गई, वहीं 2,224 शेयरों में गिरावट दर्ज हुई और 135 शेयरों में कोई खास बदलाव नहीं आया। दिन की शुरुआत में, सेंसेक्स अपने पिछले बंद 74,764.23 से मामूली गिरावट के साथ 74,742.54 पर खुला। दिन के कारोबार में इसने 74,910.96 का उच्चतम स्तर भी छुआ। वहीं, निफ्टी 50 अपने पिछले बंद 23,431.50 से 15 अंक उछलकर 23,446.60 पर खुला, जो बाजार में शुरुआती आशावाद को दर्शाता है। निफ्टी ने दिन के कारोबार में 23,494.95 का उच्चतम स्तर देखा।वहीं व्यापक बाजारों का प्रदर्शन हालांकि उतना मजबूत नहीं रहा। निफ्टी मिडकैप इंडेक्स 0.38 फीसदी की गिरावट के साथ बंद हुआ, जबकि निफ्टी स्मॉलकैप में भी 0.07 फीसदी की मामूली गिरावट दर्ज की गई। क्षेत्रवार प्रदर्शन की बात करें तो, निफ्टी मीडिया, निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज, निफ्टी पीएसयू बैंक और निफ्टी प्राइवेट बैंक ने बेहतर प्रदर्शन किया और बढ़त दर्ज की। इसके विपरीत, निफ्टी मेटल, निफ्टी फार्मा, निफ्टी ऑटो, निफ्टी हेल्थकेयर और निफ्टी एफएमसीजी जैसे सेक्टरों में गिरावट का रुख रहा, जिससे पता चलता है कि यह उछाल कुछ खास क्षेत्रों तक ही सीमित रहा।प्रमुख निफ्टी 50 इंडेक्स के भीतर, एचसीएल टेक, हिंडाल्को और टाटा स्टील जैसे शेयरों को सबसे ज्यादा नुकसान उठाना पड़ा, जो बाजार में कुछ बड़ी कंपनियों पर दबाव को दर्शाता है। वहीं, एचडीएफसी लाइफ, पावरग्रिड, ओएनजीसी, भारतीय एयरटेल और टेक महिंद्रा के शेयरों में निवेशकों ने सबसे अधिक खरीदारी की, जिससे इन कंपनियों के शेयर बढ़त पर बंद हुए।

सेबी ने कृषि जिंस वायदा कारोबार के नियम सरल बनाए

अधिकतम सौदों की सीमा में संशोधन और उल्लंघन पर जुर्माने की ऊपरी सीमा तय

नई दिल्ली ।

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) ने कृषि जिंस वायदा कारोबार को सुगम बनाने के उद्देश्य से ग्राहकों के लिए सौदों की अधिकतम सीमा में संशोधन किया है। इसके साथ ही, नियामक ने नियमों के उल्लंघन पर लगने वाले जुर्माने की अधिकतम सीमा भी तय कर दी है। यह कदम बाजार में कारोबार को बढ़ावा देने और पुरानी बाजार परिस्थितियों के आधार पर तय की गई 2017 की सीमाओं की समीक्षा के बाद उठाया गया है। नए नियमों के तहत, व्यापक जिंसों के लिए ग्राहकों के स्तर पर सौदों की अधिकतम सीमा डिलिवरी योग्य आपूर्ति मात्रा का दो प्रतिशत होगी। वहीं, सीमित जिंसों के लिए यह एक प्रतिशत और संवेदनशील जिंसों के लिए 0.5 प्रतिशत निर्धारित की गई है। सेबी ने व्यापक जिंस की परिभाषा भी संशोधित की है, जिसके अनुसार अब वह जिंस जो संवेदनशील न हो और जिसकी औसत डिलिवरी योग्य आपूर्ति पिछले पांच वर्षों में कम से कम 10 लाख टन या 5,000 करोड़ रुपए मूल्य की रही हो, व्यापक मानी जाएगी। नियामक

ने नियमों के उल्लंघन पर लगने वाले जुर्माने की गणना के लिए भी स्पष्ट दिशा-निर्देश दिए हैं। अब यह जुर्माना उल्लंघन की अतिरिक्त सीमा और उल्लंघन जारी रहने के दिनों की संख्या के आधार पर तय होगा। हालांकि, इसकी अधिकतम सीमा तय कर दी गई है, जैसे दो प्रतिशत से अधिक के उल्लंघन पर अधिकतम दो लाख रुपये और दो प्रतिशत तक के उल्लंघन पर अधिकतम 10,000 रुपये का जुर्माना लगेगा। सदस्यों को अगले कारोबारी दिन तक अतिरिक्त सीमा को निर्धारित दायरे में लाना होगा, अन्यथा शेयर बाजार बिना सूचना के अतिरिक्त सौदे समाप्त कर सकता है।

रुपया गिरावट पर बंद

मुंबई ।

अमेरिकी डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपया गरुवार को 51 पैसे की गिरावट के साथ ही 95.59 पर बंद हुआ। रुपया गुरुवार को शुरुआती कारोबार में 25 पैसे टूटकर अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 95.33 पर आ गया। विदेशी मुद्रा कारोबारियों ने बताया कि कच्चे तेल की ऊंची कीमतों और डॉलर की लगातार मांग का निवेशकों की धारणा पर असर पड़ा। अंतरबैंक विदेशी मुद्रा विनिमय बाजार में रुपया 95.15 प्रति डॉलर पर खुला। इसके बाद यह और टूटकर अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 95.33 पर आ गया जो पिछले बंद भाव से 25 पैसे की गिरावट है। रुपया बुधवार को 34 पैसे टूटकर 95.08 प्रति डॉलर पर बंद हुआ था। इस बीच दुनिया की छह प्रमुख मुद्राओं के मुकाबले अमेरिकी डॉलर की स्थिति को दिखाने वाला डॉलर सूचकांक 0.09 फीसदी की गिरावट के साथ 98.72 पर रहा।

रेलवे का मेगा विस्तार- 9 राज्यों में 20,804 करोड़ की 8 मल्टी-ट्रैकिंग परियोजनाओं को मंजूरी

दक्षिणी, पूर्वी और मध्य भारत में लगभग 1200 किलोमीटर नए ट्रैक जुड़ेंगे

नई दिल्ली ।

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने देश के 9 राज्यों में फैली 8 महत्वपूर्ण रेल मल्टी-ट्रैकिंग परियोजनाओं को हरी झंडी दे दी है। अनुमानित 20,804 करोड़ रुपये की लागत वाली इन परियोजनाओं का उद्देश्य भारतीय रेलवे के अत्यधिक व्यस्त नेटवर्क की क्षमता को बढ़ाना, कनेक्टिविटी में सुधार करना और माल ढुलाई को गति देना है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इस ऐतिहासिक फैसले की घोषणा की। इन परियोजनाओं में विभिन्न राज्यों में तीसरी और चौथी लाइनें बिछाने के साथ-साथ दोहरीकरण का कार्य भी शामिल है। दक्षिणी भारत में तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तेलंगाना के 17 जिलों में अराक्कोणम - रेनीगुंटा तीसरी और चौथी लाइन, बंगारपेट तीसरी और चौथी लाइन, होसुर - ओमालूर ट्रैक का दोहरीकरण, सेलम - करूर - डिंडिगुल दोहरीकरण और सिकंदराबाद (घाटकेसर) - काजीपेट मल्टी-ट्रैकिंग जैसी 5 परियोजनाएं भारतीय रेलवे नेटवर्क में लगभग 540 किलोमीटर का इजाफा करेंगी। इसी तरह, पूर्वी और पूर्वी मध्य इलाकों में पश्चिम बंगाल, झारखंड, ओडिशा, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के 14 जिलों में खड़गपुर - झारसुगुड़ा (बागडेही) चौथी लाइन, कटनी - पेंड्रा रोड चौथी लाइन और बिलासपुर (उसलापुर) - पेंड्रा रोड तीसरी लाइन जैसी परियोजनाएं लगभग 656 किलोमीटर का अतिरिक्त ट्रैक जोड़ेंगी। कुल मिलाकर, ये पहल भारतीय रेलवे के मौजूदा नेटवर्क में 1200 किलोमीटर से अधिक की वृद्धि करेंगी। मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि सरकार की योजना भीड़भाड़ वाले रेल नेटवर्क में कम से कम 4 लाइनें बनाने की है, और ये परियोजनाएं उसी दिशा में एक कदम हैं। इन परियोजनाओं से 9 राज्यों के लगभग 1 करोड़ लोगों को बेहतर कनेक्टिविटी मिलेगी, प्रमुख महानगरों में भीड़ कम होगी और 7.4 करोड़ टन अतिरिक्त माल ढुलाई की उम्मीद है, जिससे देश की आर्थिक गतिविधियों को और बढ़ावा मिलेगा।

मध्य प्रदेश में निवेश की बहार- दुबई से 53,000 करोड़ से अधिक के प्रस्ताव

ग्रीन हाइड्रोजन, एआइ, सौर ऊर्जा, स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग जैसे अत्याधुनिक क्षेत्रों में बड़े समूह करेंगे निवेश

नई दिल्ली ।

मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव की दुबई यात्रा राज्य के लिए बड़ी आर्थिक सफलता लेकर आई है। उनकी वैश्विक निवेशकों से हुई वन-टू-वन बैठकों के परिणामस्वरूप 53,000 करोड़ रुपये से अधिक के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं, जिनमें ग्रीन हाइड्रोजन, सौर ऊर्जा, एआई और डेटा सेंटर, स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग जैसे भविष्य के क्षेत्रों पर विशेष जोर है। मुख्यमंत्री मोहन यादव की हालिया दुबई यात्रा के दौरान विभिन्न वैश्विक निवेशकों और औद्योगिक समूहों के साथ हुई बैठकों से मध्य प्रदेश को 53,000 करोड़ रुपये से अधिक के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। इन प्रस्तावों में ग्रीन हाइड्रोजन, सौर ऊर्जा, एआई और डेटा सेंटर, स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग, ई-मोबिलिटी, इलेक्ट्रॉनिक्स, लॉजिस्टिक्स, स्वास्थ्य, शिक्षा, पर्यटन और रियल एस्टेट जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्र शामिल हैं। इनमें सबसे बड़ा प्रस्ताव राणा होल्डिंग्स लिमिटेड की ओर से आया है, जिसमें करीब 35,200 करोड़ रुपये का निवेश संभावित है। इसमें 2,000 मेगावॉट का सौर ऊर्जा पोर्टफोलियो, 200 मेगावॉट का ग्रीन हाइड्रोजन संयंत्र, 50 मेगावॉट क्षमता का एआई एवं कंप्यूट डेटा सेंटर (जिसे 200 मेगावॉट तक विस्तारित किया जा सकेगा), 30,000 एमटीपीए क्षमता का क्रिटिकल मिनरल्स रिकवरी कॉम्प्लेक्स तथा एकीकृत स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग हब स्थापित करने की योजना है। इसी तरह एनआईडीआई सर्विसेज डीएमसीसी/एससीएनईएलएल के निवेशकों ने औद्योगिक स्तर के एआई कंप्यूट कैंपस और सॉवरेन एआई फैक्ट्री परियोजना में 18 हजार करोड़ रुपये के निवेश की योजना पेश की है, जिसे भविष्य में 100 मेगावॉट से अधिक तक बढ़ाया जा सकेगा। अन्य महत्वपूर्ण बैठकों में क्रेसेंट ग्रुप के साथ नवीकरणीय ऊर्जा और लॉजिस्टिक्स; प्योर हेल्थ के साथ मल्टी स्पेशियलिटी अस्पताल और डिजिटल हेल्थ; शराफ ग्रुप के साथ मल्टीमॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क और पर्यटन; चोइथराम समूह के साथ खाद्य प्रसंस्करण तथा डीपी वर्ल्ड के साथ पवारखेड़ा लॉजिस्टिक्स कॉम्पोजिट हब पर भी चर्चा हुई। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने दुबई में इन्वेस्ट इन मध्यप्रदेश- इंटरैक्टिव सेशन के दौरान निवेशकों को राज्य के अनुकूल औद्योगिक वातावरण का भरोसा दिलाया। उन्होंने बताया कि उद्योगों के विकास के लिए 2,700 से अधिक नियम और लगभग 900 कानूनों को समाप्त कर प्रक्रिया सरल की गई है।

एसआईपी में रिकॉर्ड उछाल, निवेशकों का दीर्घकालिक भरोसा बढ़ा

बाजार उतार-चढ़ाव के बावजूद वित्त वर्ष 26 में एसआईपी ने छुआ नया मुकाम

नई दिल्ली ।

शेयर बाजार में जारी उठा-पटक और एसआईपी खाते बंद होने की बढ़ती संख्या के बावजूद, वित्त वर्ष 2026 में शुद्ध एसआईपी (सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान) निवेश ने रिकॉर्ड 2 लाख करोड़ रुपये का आंकड़ा छू लिया है। भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) की सालाना रिपोर्ट के मुताबिक, यह आंकड़ा पिछले तीन वर्षों में सबसे अधिक है और भारतीय खुदरा निवेशकों के मजबूत दीर्घकालिक निवेश नजरिए को दर्शाता है। सेबी के आंकड़ों के अनुसार वित्त वर्ष 2026 में कुल 3.5 लाख करोड़ रुपये के सकल एसआईपी निवेश का 56 प्रतिशत हिस्सा शुद्ध निवेश रहा, जो वित्त वर्ष 2025 के 54 प्रतिशत से अधिक है। शुद्ध एसआईपी निवेश का अर्थ सकल निवेश में से एसआईपी खातों से निकाली गई राशि (निवेश निकासी) को घटाने के बाद बची रकम है। रिपोर्ट बताती है कि वित्त वर्ष 2026 में एसआईपी खातों से कुल 1.5 लाख करोड़ रुपये की निकासी हुई, जो वित्त वर्ष 2025 के 1.3 लाख करोड़ रुपये से 15 प्रतिशत अधिक है। हालांकि, यह वृद्धि पिछले तीन सालों में सबसे धीमी रही। वित्त वर्ष 2024 में निकासी में 57 प्रतिशत और वित्त वर्ष 2025 में 18 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई थी। इससे भी महत्वपूर्ण, वित्त वर्ष 2026 में निकासी की वृद्धि दर सकल निवेश की 21 प्रतिशत वृद्धि से काफी कम थी। म्युचुअल फंड अधिकारियों का मानना है कि शुद्ध एसआईपी निवेश में यह बढ़ोतरी खुदरा निवेशकों में लंबी अवधि के लिए निवेश करने की सोच के लगातार बढ़ने का परिणाम है। यह रुझान बाजार की अस्थिरता के बावजूद निवेशकों के परिपक्व व्यवहार को रेखांकित करता है।

त्योहारी सीजन से पहले स्मार्टफोन महंगे

- भारत में कीमतों में रिकॉर्ड 21 फीसदी की उछाल, बिक्री 45 फीसदी गिरी

नई दिल्ली ।

त्योहारी सीजन से ठीक पहले नया स्मार्टफोन खरीदने की सोच रहे उपभोक्ताओं को बड़ा झटका लगा है। एक रिपोर्ट के अनुसार, साल 2026 में भारत में स्मार्टफोन की औसत खुदरा कीमतों में 21 फीसदी की रिकॉर्ड वृद्धि दर्ज की गई है, जो दुनिया के किसी भी बड़े बाजार में सबसे तेज उछाल है। वैश्विक स्तर पर औसत कीमतों में 15 फीसदी की बढ़ोतरी हुई है, लेकिन भारत में यह आंकड़ा कहीं अधिक है, जिससे सीधे भारतीय ग्राहकों की जेब पर अतिरिक्त बोझ पड़ा है। स्मार्टफोन की कीमतों में इस भारी वृद्धि के पीछे मुख्य कारण उसमें लगने वाली मेमोरी (डीआरएएम और एनएएनडी चिप) की बढ़ती लागत है। सितंबर 2025 के बाद से इन चिप्स की कीमतें लगभग चार गुना बढ़ चुकी हैं। दरअसल, दुनियाभर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) इंफ्रास्ट्रक्चर की भारी मांग के कारण सेमीकंडक्टर निर्माता अपनी उत्पादन क्षमता को एआई सर्वरों में उपयोग होने वाली हाई-बैंडविड्थ मेमोरी के निर्माण पर केंद्रित कर रहे हैं, जिससे स्मार्टफोन में लगने वाली पारंपरिक मेमोरी की आपूर्ति घट गई है। भारतीय बाजार का 51 फीसदी से अधिक हिस्सा 20,000 रुपये से कम कीमत वाले लो और मिड-रेंज फोनों का है। चूंकि बजट फोन में कंपनियों का मार्जिन न के बराबर होता है, इसलिए उत्पादन लागत का पूरा बोझ सीधे भारतीय ग्राहकों पर डाल दिया गया है। इसके विपरीत, पश्चिमी देशों में जहां प्रीमियम फोन अधिक बिकते हैं और कंपनियों के पास बेहतर मार्जिन होता है, वहां वे अतिरिक्त लागत का कुछ हिस्सा खुद वहन कर लेती हैं। इस मूल्य वृद्धि का सीधा असर बिक्री पर पड़ा है। जून तिमाही में 15,000 रुपये से कम कीमत वाले स्मार्टफोन की बिक्री में 45 फीसदी की भारी गिरावट आई है। कंपनियों ने कीमतें थामने के लिए कई फोनों के मेमोरी कॉन्फ़िगरेशन तक घटा दिए हैं, और 2026 में लॉन्च हुए नए मॉडल्स पिछले साल के मुकाबले 25 फीसदी तक महंगे हो चुके हैं।

Web site : www.krantisamay.com & epaper.krantisamay.com www.facebook.com/krantisamay1 www.twitter.com/krantisamay1

35 महीने से वनडे क्रिकेट की 'बेताज बादशाह' टीम इंडिया, टी20 में भी हुकूमत कायम

नई दिल्ली। वनडे क्रिकेट में भारत का वर्चस्व लगातार कायम है। 50 ओवर के फॉर्मेट में पिछले 35 महीनों से दुनिया की बड़ी से बड़ी टीम भी भारत से नंबर एक का ताज नहीं छिन सकी है। सिर्फ वनडे ही नहीं, बल्कि क्रिकेट के सबसे छोटे फॉर्मेट यानी टी20 में भी भारत का दबदबा लगातार बना हुआ है। वनडे क्रिकेट में भारतरीय टीम की बादशाहत सितंबर 2023 से कायम है। भारत ने पाकिस्तान से नंबर एक की कुर्सी छीनी थी और उसके बाद से किसी भी टीम को इस पोजीशन के आसपास तक नहीं भटकने दिया है। भारतीय टीम के अभी कुल 116 रेटिंग प्वाइंट्स हैं। भारत के बाद फिलहाल आईसीसी की ताजा रैंकिंग में न्यूजीलैंड दूसरे नंबर पर है, जिसके कुल रेटिंग प्वाइंट 109 हैं। वहीं, ऑस्ट्रेलिया 102 रेटिंग प्वाइंट्स के साथ तीसरे नंबर पर काबिज है। 2023 से लेकर अब तक 50 ओवर के फॉर्मेट में भारतीय टीम का प्रदर्शन लाजवाब रहा है। 2023 में टीम इंडिया ने कुल 35 वनडे मैच खेले और इस दौरान 27 मुकाबलों में जीत हासिल की, जबकि महज 7 मैचों में टीम को हार का सामना करना पड़ा। साल 2024 में भारतीय टीम ने सिर्फ 3 ही वनडे मुकाबले खेले। इस दौरान टीम को 2 मैचों में हार का सामना करना पड़ा, तो एक मुकाबला टाई रहा।

टीम इंडिया के लिए साल 2025 वनडे फॉर्मेट में बेमिसाल रहा। साल की शुरुआत में ही भारतीय टीम ने चैंपियंस ट्रॉफी के खिताब पर कब्जा जमाते हुए अपनी बादशाहत साबित की। 2025 में भारत ने कुल मिलाकर 14 वनडे मुकाबले खेले और टीम को 11 में जीत नसीब हुई। वहीं, सिर्फ 3 ही मैचों में टीम इंडिया को हार का सामना करना पड़ा। भारत का जीत प्रतिशत 78.57 का रहा। साल के आखिरी में बीसीसीआई ने रोहित शर्मा के हाथों से वनडे टीम की कमान लेकर शुभमन गिल के हाथों में सौंपी। गिल की कप्तानी में भले ही टीम इंडिया को ऑस्ट्रेलिया की धरती पर वनडे सीरीज में हार मिली, पर टीम का प्रदर्शन बेहद सराहनीय रहा।

साल 2026 में भारत ने अभी तक कुल 9 वनडे मैच खेले हैं और इस दौरान टीम को 5 में जीत, जबकि 4 मुकाबलों में हार का सामना करना पड़ा है। इस दौरान भारत को इंग्लैंड की सरजमीं पर वनडे सीरीज गंवानी पड़ी। हालांकि, नए-नवेले कप्तान गिल की अगुवाई में भारत ने इस फॉर्मेट में हर बड़ी टीम को कड़ी टक्कर जरूर दी है।

टी20 में भी भारत का दबदबा लगातार कायम रखा है। भारतीय टीम फरवरी 2022 से क्रिकेट के सबसे लंबे फॉर्मेट में जुलाई 2026 तक नंबर वन रही। इसके बाद इंग्लैंड के हाथों पांच मैचों की टी20 सीरीज 0-4 से गंवाने के बाद टीम की 1600 दिनों से चली आ रही बादशाहत कुछ दिनों के लिए इंग्लिश टीम ने खत्म की। हालांकि, जिम्बाब्वे के खिलाफ दूसरे टी20 में बड़ी जीत के साथ ही भारत ने एक बार फिर टी20 के किंग का ताज पहन लिया।

टी20 फॉर्मेट में नंबर वन रहते हुए भारत ने लगातार दो बार टी20 विश्व कप के खिताब को अपने नाम किया। 2024 में रोहित शर्मा ने अपनी कप्तानी में टीम को चैंपियन बनाया, तो 2026 में सूर्यकुमार यादव की अगुवाई में टीम इंडिया वर्ल्ड चैंपियन बनी। भारत पहला ऐसा देश बना, जिसने सफलतापूर्वक अपने खिताब का बचाव किया और अपने ही घर में टी20 वर्ल्ड कप जीता।

सार-समाचार

अफगानिस्तान के खिलाफ टी20 सीरीज खेल सकते हैं वाशिंगटन व रेड्डी

नई दिल्ली। भारत और अफगानिस्तान के बीच 13 सितंबर से टी20 सीरीज की शुरुआत होने जा रही है, जिससे पहले ऑफ-स्पिन बॉलिंग ऑलराउंडर वाशिंगटन सुंदर और सीम-बॉलिंग ऑलराउंडर नितिश कुमार रेड्डी को फिटनेस हासिल कर चुके हैं। ये दोनों खिलाड़ी गुरुवार को टीम के साथ जुड़ेंगे। एक सूत्र ने बुधवार को 'आईएएनएस' को बताया, 'सुंदर और रेड्डी कुछ समय पहले ही पूरी तरह फिट हो गए थे। दोनों ने बेंगलुरु में बीसीसीआई सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में अपने फिटनेस टेस्ट और मैच सिमुलेशन पास कर लिए हैं।'

उल्लेखनीय है कि वाशिंगटन सुंदर हैमस्ट्रिंग की चोट के कारण सुंदर श्रीलंका में दो मैचों की टेस्ट सीरीज में नहीं खेल सके थे। वहीं, रेड्डी ने आखिरी बार जून में अफगानिस्तान के खिलाफ घरेलू वनडे सीरीज में खेला था, जिसके बाद उनके बाएं क्वाड्रिसेप्स की चोट बढ़ गई और वे आयरलैंड, इंग्लैंड और श्रीलंका के दौरे पर नहीं जा पाए थे। इंग्लैंड के खिलाफ दूसरे वनडे में फील्डिंग के दौरान घुटने में लगी चोट के कारण जसप्रीत बुमराह खेल से बाहर हैं। ऐसे में उनके तीन मुकाबलों की टी20 सीरीज के लिए टीम में शामिल होने के बारे में अभी कोई पक्की खबर नहीं है। सीम-बॉलिंग ऑलराउंडर हर्षित राणा की भागीदारी पर भी संशय बना हुआ है, जो हैमस्ट्रिंग की चोट से उबर रहे हैं। अगर इन दोनों में से कोई भी राष्ट्रीय टीम के साथ नहीं जुड़ पाता, तो तेज गेंदबाज प्रिंस यादव को आखिरी समय में टीम में शामिल किया जा सकता है। अफगानिस्तान के खिलाफ टी20 सीरीज के बाद भारतीय टीम एशियन गेम्स 2026 के लिए जापान रवाना होगी। टीम इंडिया 22 सितंबर को सानो इंटरनेशनल क्रिकेट ग्राउंड पर मेजबान जापान के खिलाफ टी20 मैच खेलेगी, जिसके बाद 28 सितंबर को कोरोजी स्पोर्ट्स पार्क में एशियन गेम्स में अपने गोल्ड मेडल का बचाव करने का अभियान शुरू करेगी।

जूनियर विमेंस हॉकी एशिया कप: शान से सेमीफाइनल में पहुंचीं भारत की बेटियां

पाकिस्तान को 19-0 से रौंदा

मोकी (चीन)। भारतीय टीम ने विमेंस जूनियर हॉकी एशिया कप 2026 के क्वार्टर फाइनल मुकाबले में पाकिस्तान को 19-0 से रौंद दिया है। इस जीत के साथ ही भारत ने सेमीफाइनल का टिकट भी हासिल कर लिया है। डिफेंडिंग चैंपियन भारत ने मैच की शुरुआत से ही शानदार खेल दिखाया। टीम को पहला गोल करने में सिर्फ सात मिनट लगे, जब पूजा साहू ने गेंद को गोलपोस्ट में पहुंचाते हुए टीम को 1-0 की बढ़त दिलाई। दो मिनट बाद रोशनी ऐंड ने भारत की बढ़त को दोगुना कर दिया। इसके बाद भारतीय खिलाड़ियों ने लगातार अटैक किया, जिससे पाकिस्तान की टीम पर दबाव बढ़ता चला गया। अगले पांच मिनट में भारत ने चार और गोल दाग दिए। तनुश्री दिनेश काडू ने 11वें मिनट में, सुखवीर कौर ने 13वें मिनट में और सानिका चंद्रकांत माने ने भी 13वें मिनट में गोल किया।

मधु सिदार और गीता यादव ने भी गोल कर टीम की बढ़त और बढ़ा दी। वहीं, सानिका माने ने 23वें मिनट में अपना दूसरा गोल करके भारत की मजबूत स्थिति को और मजबूत कर दिया। भारत ने पहले हाफ में अपना दबदबा पूरी तरह बनाए रखा। तनुजा टोप्पो और पूजा मलिक ने गोल करके टीम की बढ़त को और मजबूत किया।

इसके बाद 33वें मिनट में पूर्णिमा यादव ने भी गोल दागा, जिससे भारत ने हाफ-टाइम तक 10-0 की बड़ी बढ़त हासिल कर ली।

दूसरे हाफ की शुरुआत के बाद भी भारतीय टीम ने आक्रामक खेल जारी रखा। 39वें मिनट में मधु सिदार ने एक और गोल किया और एक मिनट बाद सुप्रिया ने भी मैच का अपना पहला गोल दागा। इसके बाद पूजा मलिक ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 49वें और 51वें मिनट में लगातार दो गोल किए और अपनी हैट्रिक पूरी की। भारत ने पूरे मैच में पाकिस्तान को वापसी का कोई मौका नहीं दिया।

कृष्णा शर्मा और बिनिमा धन ने भी गोल किए, जिससे टीम की बढ़त लगातार बढ़ती गई। सुप्रिया ने 54वें मिनट में अपना दूसरा गोल दागा, जबकि रोशनी ने मैच के आखिरी मिनट में गोल करके अपना दूसरा गोल पूरा किया और भारत की शानदार जीत पर मुहर लगा दी। भारत की यह 19-0 की बड़ी जीत कोई हैरानी की बात नहीं थी, क्योंकि टीम ने ग्रुप चरण में भी बेहतरीन प्रदर्शन किया था। भारत ने जापान, मलेशिया और साउथ कोरिया जैसी मजबूत टीमों को हराकर अपने ग्रुप में शीर्ष स्थान हासिल किया था।

अब भारतीय टीम सेमीफाइनल में साउथ कोरिया और मलेशिया के बीच होने वाले क्वार्टर फाइनल के विजेता से भिड़ेगी। मौजूदा चैंपियन भारत लगातार तीसरी बार जूनियर महिला एशिया कप का खिताब जीतने से सिर्फ दो जीत दूर है। टीम ने 2023 और 2024 में भी यह ट्रॉफी अपने नाम की थी।

जूनियर एशिया कप हॉकी

अनमोल एक्का के छह गोल की मदद से भारतीय पुरुष टीम सेमीफाइनल में पहुंची

मोकी। डिफेंडिंग चैंपियन भारत ने बुधवार को यहां अपने आखिरी पूल ए मैच में चीनी ताइपे को 15-0 से आसानी से हराकर एएचएफ जूनियर एशिया कप 2026 के सेमीफाइनल में जगह बना ली। भारत की तरफ से कप्तान कप्तान अनमोल एक्का ने छह गोल किए। एक्का ने सभी गोल पेनल्टी कॉर्नर से किए। एक्का के गोलों की वजह से हीं भारत ने बिना गोल वाले शुरुआती क्वार्टर को एकतरफा मुकाबले में बदल दिया। इस जीत से भारत तीन जीत और एक ड्रॉ से 10 पॉइंट्स के साथ पूल ए में टॉप पर पहुंच गया। मैच में भारत ने गेंद पर दबदबा बनाए रखा और शुरुआती 15 मिनट में कई मौके बनाए, लेकिन चीनी ताइपे के मजबूत डिफेंस को भेद नहीं पाया। आखिरकार 17वें मिनट में

सफलता मिली जब आर्यन जेस ने पहला गोल किया, और एक मिनट बाद प्रभदीप सिंह ने बढ़त दोगुनी कर दी। 22वें मिनट में गुरसेवक सिंह ने स्कोर 3-0 कर दिया, जिसके तीन मिनट बाद एक्का ने अपना पहला पेनल्टी कॉर्नर गोल में बदला। अर्जुन संतोष हरगुडे ने 28वें मिनट में एक और गोल किया, और कुछ ही देर बाद एक्का ने फिर गोल किया, जिससे भारत हाफ-टाइम में 6-0 की बढ़त के साथ गया।

तीसरा क्वार्टर पूरी तरह से भारत के नाम रहा। एक्का ने अपनी हैट्रिक पूरी करने के लिए दो शुरुआती पेनल्टी कॉर्नर गोल में बदले और फिर एक और गोल करके अपनी संख्या चार कर ली। अजीत यादव ने भी 35वें मिनट में गोल किया, जिसके बाद एक्का ने 45वें मिनट में फिर से गोल करके अपना स्कोर पांच कर दिया और भारत को डबल फिगर में पहुंचा दिया।

आखिरी क्वार्टर में हरपाल ने 48वें मिनट में गोल किया, जिसके तीन मिनट बाद एक्का ने एक और सफल पेनल्टी कॉर्नर के साथ अपना शानदार छह गोल का आंकड़ा पूरा किया। हरपाल ने इसके तुरंत बाद अपना दूसरा गोल किया, जबकि आर्यन जेस ने मैच का अपना दूसरा गोल करके भारत को 15-0 से जीत दिलाई।

'वह जल्द ही अपनी बेस्ट फॉर्म में लौटेंगे'

इंटर के खिलाफ खराब प्रदर्शन के बाद जोस मोरिन्हो ने किया विनीसियस का बचाव

नई दिल्ली। रियल मैड्रिड के स्टार खिलाड़ी विनीसियस जूनियर को लेकर रियल मैड्रिड के मैनेजर जोस मोरिन्हो ने भरोसा जताया है। मोरिन्हो का कहना है कि विनीसियस जल्द ही अपनी पुरानी फॉर्म में लौटेंगे। चैंपियंस लीग में इंटर के खिलाफ रियल मैड्रिड की 2-1 की जीत के दौरान कुछ घरेलू दर्शकों ने विनीसियस के खिलाफ हूटिंग की थी। हालांकि, मोरिन्हो का मानना है कि वह एक बेहतरीन खिलाड़ी हैं और जल्द ही अपने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन से आलोचकों का जवाब देंगे। बुधवार को सैंटियागो बर्नबेउ में 87वें मिनट में विनीसियस को सब्स्टीट्यूट किया गया, जिससे कुछ समर्थक उनके प्रदर्शन से नाराज दिखे। ब्राजील का यह खिलाड़ी इंटर के मजबूत डिफेंस के सामने कुछ खास प्रभाव छोड़ने में नाकाम रहा। हालांकि, मोरिन्हो ने विंगर की आलोचना करने से इनकार किया और इसके बजाय टीम के लिए उनकी मेहनत की तारीफ की। मैच के बाद मोरिन्हो ने पत्रकारों से कहा, 'वह अपनी बेस्ट फॉर्म में नहीं हैं, और उन्हें यह पता है, लेकिन वह उस विनीसियस जैसा बनने के लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं जो मैच का नतीजा तय करते हैं। अपनी बेस्ट फॉर्म में न होने के बावजूद वह पहले से कहीं अधिक मेहनत कर रहे हैं।'

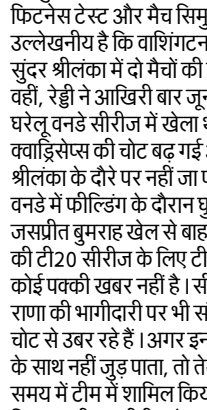

पुर्तगाली मैनेजर ने थकान को भी एक कारण बताया जिसकी वजह से विनीसियस मैच के आखिर में डिफेंस में अपना काम ठीक से नहीं कर पाए। उन्होंने कहा, 'जब वह पीछे आकर डिफेंस नहीं कर पाए, तो उसकी वजह थकान थी। मुझे इसकी बहुत कद्र है। मैं विनीसियस का बहुत सम्मान करता हूं। वह समय जरूर आएगा जब वह मैच का नतीजा तय करेंगे और हमें जीत दिलाएंगे।'

मोरिन्हो ने विनीसियस के प्रदर्शन की आलोचना का बचाव करते हुए इंटर की तकनीकी रणनीति के खिलाफ रियल मैड्रिड के अटैकर्स को हुई मुश्किलों के बारे में भी बताया। उन्होंने कहा, 'अगर वह मेहनत करते हैं, तो उन्हें हमेशा मेरा समर्थन मिलेगा। उन्होंने टीम के लिए बहुत मेहनत की। ऐसी टीम के खिलाफ खेलना विंगर्स के लिए बहुत मुश्किल होता है जो पीछे तीन डिफेंडर और विंग-बैक का इस्तेमाल करती है।'

रियल मैड्रिड के बॉस का मानना ?

एशियन गेम्स 2026

जेमिमा की जगह प्रतिका हुई भारतीय टीम में शामिल

नई दिल्ली। जापान के आइची-नागोया में होने वाले एशियन गेम्स 2026 के लिए भारतीय महिला क्रिकेट टीम में टॉप-ऑर्डर की बल्लेबाज प्रतिका रावल को चोटिल जेमिमा रोड्रिग्स की जगह शामिल किया गया है। जेमिमा, जो भारत के मिडिल ऑर्डर की अहम खिलाड़ी हैं अभी भी हैमस्ट्रिंग की चोट से उबर रही हैं। उन्हें यह चोट पिछले महीने की शुरुआत में 'द हंड्रेड' टूर्नामेंट में 'सदर्न ब्रेव' के लिए खेलते हुए लगी थी। इस चोट के कारण जेमिमा दुबई में चल रहे महिला एशिया कप 2026 से भी बाहर हो गई थीं। जब एशिया कप टीम में जेमिमा की जगह प्रतिका को शामिल करने की घोषणा की गई थी, तब उसके बाद होने वाले एशियन गेम्स के लिए उनकी जगह लेने वाली खिलाड़ी के बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई थी। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) के एक सूत्र ने बुधवार को 'आईएएनएस' को बताया, 'प्रतिका एशियन गेम्स 2026 में जेमिमा रोड्रिग्स की जगह जापान जाएंगी। एशियन गेम्स के लिए सौंपी गई 15 सदस्यीय टीम में उनका नाम शामिल है।'

प्रतिका ने दुबई में चल रहे एशिया कप में अपना टी20 इंटरनेशल डेब्यू किया और भारतीय टीम मैनेजमेंट ने उन्हें नंबर तीन पोजीशन पर खेलने के लिए चुना। टूर्नामेंट के लीग स्टेज में प्रतिका ने 22, 10 और 4 रन बनाए हैं। एशिया कप के लिए भारतीय टी20 इंटरनेशनल टीम में उन्हें अचानक तब बुलाया गया जब वह इंग्लैंड में 'वन डे कप' में 'वार्विकशायर' के लिए खेलने की तैयारी कर रही थीं। हाल ही में टी20 इंटरनेशनल डेब्यू करने से पहले प्रतिका ने नवंबर 2024 के बाद से कोई प्रतिस्पर्धी टी20 मैच नहीं खेला था, महिला वनडे वर्ल्ड कप 2025 में बांग्लादेश के खिलाफ मैच के दौरान उनके टखने में चोट लग गई थी। इस चोट की वजह से उन्हें लंबे समय तक मैदान से बाहर रहना पड़ा और वह काफी समय तक क्रिकेट नहीं खेल सकीं।

उस चोट के कारण प्रतिका महिला प्रीमियर लीग (डब्ल्यूपीएल) का 2026 एडिशन भी नहीं खेल पाईं। उन्हें पिछले साल नई दिल्ली में हुए प्लेयर ऑक्शन में यूपी वॉरियर्स ने 50 लाख रुपये में खरीदा था। भारतीय टीम मैनेजमेंट को उम्मीद होगी कि रावल मिडिल ऑर्डर में जल्द ही अपनी लय हासिल कर लेंगी, क्योंकि गुरुवार को दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में होने वाले सेमीफाइनल में भारत का मुकाबला बांग्लादेश से होना है। एशियन गेम्स 2026 में महिला क्रिकेट प्रतियोगिता 17 से 22 सितंबर तक होगी।

एशियन गेम्स के लिए भारत की टीम

हरमनप्रीत कौर (कप्तान), स्मृति मंधाना (उप-कप्तान), शेफाली वर्मा, प्रतिका रावल, भारती फुलमाली, ऋचा घोष (विकेटकीपर), जी. कामलिनी (विकेटकीपर), दीप्ति शर्मा, राधा यादव, प्रेमा रावत, अरुंधति रेड्डी, क्रांति गौड़, रेणुका सिंह, एन. श्री चरणी और नंदिनी शर्मा।

वनडे रिकॉर्ड: डेब्यू मैच में हरमन ने जड़े 150 रन

हमवतन खिलाड़ी के 'वर्ल्ड रिकॉर्ड' की बराबरी

विंडहोक। साउथ अफ्रीका के 24 वर्षीय बल्लेबाज जॉर्डन हरमन वनडे डेब्यू मैच में सबसे बड़ी पारी खेलने के मामले में संयुक्त रूप से 'नंबर-1' बन गए हैं। बाएं हाथ के सलामी बल्लेबाज ने बुधवार को नामीबिया क्रिकेट ग्राउंड पर नामीबिया के खिलाफ 126 गेंदों में 3 छक्कों और 17 चौकों के साथ 150 रन जड़े। इसी के साथ हरमन ने हमवतन मैथ्यू ब्रीत्जके के रिकॉर्ड की बराबरी कर ली है, जिन्होंने 10 फरवरी 2025 को न्यूजीलैंड के विरुद्ध वनडे फॉर्मेट में डेब्यू करते हुए 148 गेंदों में 16 बाउंड्री के साथ 150 रन की पारी खेली थी। पुरुषों की इस लिस्ट में वेस्टइंडीज के डेसमंड हेन्स (148 बनाम ऑस्ट्रेलिया) तीसरे और अफगानिस्तान के रहमानुल्लाह गुरबाज (127 बनाम आयरलैंड) चौथे स्थान पर हैं। भारत की तरफ से केएल राहुल डेब्यू वनडे मैच में शतक लगाने वाले इकलौते खिलाड़ी हैं। टॉस गंवाकर बल्लेबाजी करने उतरी साउथ अफ्रीकी टीम ने निर्धारित ओवरों में 6 विकेट खोकर 348 रन बनाए। साउथ अफ्रीका ने महज 27 के स्कोर पर कॉनर एस्टरहुइजेन (10) का विकेट गंवा दिया था, जिसके बाद हरमन ने टोनी डी जोरजी के साथ दूसरे विकेट के लिए 166 गेंदों में 190 रन जोड़कर टीम को दोहरे शतक के पार पहुंचा दिया।

जोरजी 84 गेंदों में 8 बाउंड्री के साथ 72 रन बनाकर आउट हुए, जिसके बाद हरमन ने देवाल्ड ब्रेविस (33) के साथ तीसरे विकेट के लिए 58 रन जुटाए। टीम को हरमन के रूप में 275 के स्कोर पर तीसरा झटका लगा, जिसके बाद 292 रन तक 5 विकेट गिर गए।

इसके बाद कॉर्बिन बॉश (नाबाद 39) ने जेसन स्मिथ (15) के साथ छठे विकेट के लिए 32 गेंदों में 41 रन जुटाकर टीम को तिहरे शतक के पार पहुंचाया। नामीबिया की तरफ से रूबेन ट्रम्पेलमैन ने सर्वाधिक 4 विकेट निकाले, जबकि जेजे स्मिट और गेरहार्ड इरास्मस को 1-1 विकेट हाथ लगा।

दोनों देशों के बीच वनडे सीरीज के तीन मुकाबले 9, 11 और 13 सितंबर को खेले जाएंगे। साउथ अफ्रीका सीरीज का पहला मैच जीतकर बढ़त हासिल करना चाहेगा।

Web site : www.krantisamay.com & epaper.krantisamay.com | www.facebook.com/krantisamay1 | www.twitter.com/krantisamay1

संक्षिप्त समाचार

आपदा में मकान, सड़कें और पुल बह गए, भारत-चीन कर रहे मदद; बेली ब्रिज भेजे गए

काठमांडू, एजेंसी। नेपाल विनाशकारी बाढ़ से प्रभावित इलाकों में पुलों और सड़कों को फिर से बनाने की कोशिश में जुटा है, और भारत और चीन से मदद मांगी है। पड़ोसी देशों ने अस्थायी पुल मुहैया कराने के नेपाल के आग्रह पर सकारात्मक प्रतिक्रिया दी है। आपदा में उत्तरी और मध्य नेपाल में मकान, वाहन, सड़कें और पुल बह गए थे। रसुवा और चितवन के बीच 63 पुल में 41 पुल नष्ट हो गए और चार अन्य आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त हुए। काठमांडो पोस्ट की खबर के अनुसार, चीन मुस्तांग में कोरला सीमा चौकी पर दो बेली ब्रिज पहले ही भेज चुका है। भारत ने भी नेपाल को बेली ब्रिज उपलब्ध कराने की पेशकश की है। काठमांडो के एक बौद्ध मठ में बने राहत शिविर में इन दिनों 520 ऐसे बेघर लोगों ने शरण ले रखी है जिन्होंने अपना सब कुछ गंवा दिया है। शिविर में एक कोने में बैठे 12 वर्ष के मासूम त्सेरिंग की आंखें लगातार दरवाजे पर टिकी हैं। उसे भरोसा है कि उसके माता-पिता जल्द लौट आएंगे, लेकिन सच्चाई यही है कि वो अब इस दुनिया में नहीं हैं। नेपाल में जल प्रलय के बाद अब उत्तर-पश्चिमी हिस्से में मंगलवार रात 5.3 तीव्रता का भूकंप आया। भूकंप का केंद्र मुस्तांग जिले के लोमानथांग में था। इससे कोई हताहत नहीं है।

अमेरिका-कनाडा व्यापार युद्ध: ट्रंप के टैरिफ का कनाडा ने दिया जवाब; स्टील समेत क्या सामान महंगे होंगे

टोरंटो, एजेंसी। अमेरिका-कनाडा के बीच ट्रेड वार अब चरम पर पहुंच चुका है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और कनाडा के पीएम मार्क कार्नी के रिश्ते तल्ख होने के बीच कनाडा ने भी अमेरिका पर जवाबी टैरिफ लागू कर दिया है। कनाडाई सरकार ने कहा कि जवाबी टैरिफ 22 अगस्त से 20 अरब डॉलर के कनाडाई सामानों पर 50% टैरिफ लगाने के अमेरिका के फैसले के जवाब में उठाए गए हैं। जवाबी टैरिफ से स्टील, एल्युमीनियम, डेयरी उत्पाद (जैसे पनीर), घरेलू और कृषि उपकरण, इलेक्ट्रॉनिक्स तथा पल्प-पेपर जैसे प्रमुख अमेरिकी उद्योग प्रभावित होंगे। पिछले माह वाशिंगटन में दोनों देशों के बीच महीनों चली व्यापार वार्ता अचानक टूट गई। कनाडा ने आरोप लगाया कि अमेरिकी वार्ताकारों ने अंतिम समय में अनुचित शर्तें थोप दी थीं। ट्रंप ने कनाडा की करेंसी और अमेरिका के साथ उसके मुद्रा असंतुलन को अस्वीकार्य करार दिया, जिससे दोनों देशों के बीच कूटनीतिक तनाव और ज्यादा गहरा गया है।

ट्रंप ने पुतिन को मिलाया फोन: यूक्रेन युद्ध खत्म करने पर हुई बात, यूरोप को लेकर क्या बोले रूसी राष्ट्रपति

वाशिंगटन, एजेंसी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मंगलवार को रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से फोन पर बात की और कहा कि वह यूक्रेन में जारी युद्ध को जल्द खत्म करना चाहते हैं। रूसी राष्ट्रपति के कार्यालय क्रेमलिन पुतिन ने ट्रंप के इस रुख का समर्थन किया। क्रेमलिन की ओर से जारी बयान में कहा गया कि युद्ध समाप्त होने से अमेरिका और रूस के संबंध पूरी तरह सामान्य करने की राह खुलेगी। क्रेमलिन के मुताबिक, पुतिन और ट्रंप के बीच करीब एक घंटे बातचीत हुई। यह बातचीत अमेरिका के विशेष दूत स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशनर की हालिया मास्को और कीव की यात्रा के बाद हुई। दोनों दूत युद्ध खत्म करने के लिए रुकी हुई बातचीत को फिर शुरू कराने की कोशिश कर रहे हैं। क्रेमलिन के अधिकारी यूरी उशाकोव ने कहा, पुतिन और ट्रंप ने अमेरिकी दूतों की कोशिशों को सकारात्मक माना। पुतिन ने ट्रंप को बताया कि युद्ध खत्म करने में अमेरिका क्या भूमिका निभा सकता है और उन्हें मौजूदा युद्धक्षेत्र की स्थिति की जानकारी भी दी। उशाकोव के मुताबिक, अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप चाहते हैं कि उनके मौजूदा कार्यकाल में ही युद्ध खत्म करने की दिशा में बड़ी सफलता मिले। ट्रंप ने कहा कि युद्ध खत्म होने से दोनों देशों के व्यापार और आर्थिक संबंधों को भी बड़ा फायदा होगा। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप से फोन पर बातचीत के दौरान पुतिन ने यह भी कहा कि रूस की यूरोप के खिलाफ कोई आक्रामक मंशा नहीं है। क्रेमलिन के अनुसार, पुतिन ने कहा कि रूस से खतरे की बातें यूरोपीय देशों को यूक्रेन का समर्थन बढ़ाने और सैन्य खर्च बढ़ाने का बहाना देती हैं। रूस अपने सैन्य लक्ष्य हासिल करने के लिए प्रतिबद्ध है।

पहले मोनालिसा, अब रेनॉयर: फ्रांसीसी म्यूजियम से बेशकीमती पेंटिंग चोरी, कब-कब चुराई गई करोड़ों की कलाकृतियां

पेरिस, एजेंसी। फ्रांस के कैग्नेस-सुर-मेर शहर के मेयर ने मंगलवार को बताया कि चोरों ने फ्रेंच रिवेरा स्थित रेनॉयर म्यूजियम में सेंध लगाकर फ्रांसीसी इंप्रेशनिस्ट मास्टर ऑगस्टे रेनॉयर की चार कीमती कलाकृतियां चुरा लीं। हालांकि, भागते समय चोर दो पेंटिंग म्यूजियम के बगीचे में ही छोड़ गए। म्यूजियम में रेनॉयर की कुल 12 कलाकृतियां थीं। चोरी हुई दो पेंटिंग हैं 'पोर्ट्रेट ऑफ़ मैडम कोलोना रोमानो' और 'यंग वुमन एट द वेल' हैं। पुलिस फिलहाल चोरी को अंजाम देने वालों की तलाश में जुटी है। इस घटना के बीच आइए, दुनिया में हुई कला की कुछ दूसरी चर्चित और बड़ी चोरियों पर एक नजर डालते हैं।

इटली के म्यूजियम से रेनॉयर, सेजान और मैटिस की पेंटिंग चोरी : मार्च में चोर उत्तरी इटली के पार्मा शहर के पास स्थित एक निजी म्यूजियम, मैग्नानी रोक्का फ़ाउंडेशन से फ्रांसीसी कला जगत के तीन दिग्गजों की पेंटिंग चुराकर फरार हो गए। चोरी हुई तीन पेंटिंग में ऑगस्टे रेनॉयर की 'फिश', पॉल सेजान की 'स्टिल लाइफ़ विद चेरीज' और हेनरी मैटिस की 'ओडालिस्क ऑन द टेरेस' शामिल थीं। आकार में भले ही ये कलाकृतियां छोटी मानी जाती थीं, लेकिन इनकी कीमत लाखों यूरो आंकी गई थी।

कुछ महीनों बाद बरामद हुई तीनों कलाकृतियां : अगस्त में इटली की कैराबिनियरी यानी पुलिस बल की आर्ट रिकवरी स्क्वाड ने तीनों पेंटिंग बरामद कर लीं। चोरी के सिलसिले में संगठित अपराध गिरोह का हिस्सा माने जा रहे पांच लोगों को हिरासत में लिया गया।

लूव्र में दिनदहाड़े चोरी, नेपोलियन काल के शाही गहने ले गए चोर : अक्टूबर में दिनदहाड़े हुई एक नाटकीय चोरी में पेरिस के लूव्र म्यूजियम से फ्रांसीसी सम्राट नेपोलियन बोनापार्ट और उनके परिवार के शाही गहनों के संग्रह से नौ चीजें चुरा ली गईं। चोरों ने उस समय लूव्र को निशाना बनाया, जब म्यूज़ियम आम दर्शकों के लिए खुला हुआ था। उन्होंने म्यूज़ियम की बाहरी दीवार तक पहुंचने के लिए बास्केट लिफ्ट का इस्तेमाल किया। इसके बाद महज कुछ मिनटों में उन्होंने डिस्प्ले केस तोड़ दिए और करीब 88 मिलियन यूरो (102 मिलियन अमेरिकी डॉलर) मूल्य के गहने लेकर फरार हो गए। चोरी किए गए सामान में नीलम जड़ा एक डायडेम, एक हार और एक कान की बाली शामिल थी।

ज्यादातर गहने अब भी गायब : चोरी को अंजाम देने वाले चार लोगों के गिरोह को आखिरकार पकड़ लिया गया, लेकिन चोरी किए गए ज्यादातर गहने बरामद नहीं हो सके। केवल महारानी यूजीनी का हीरे और पन्ने जड़ा ताज ही म्यूजियम के बाहर क्षतिग्रस्त हालत में मिला। माना गया कि भागते समय चोरों से यह ताज गिर गया था। इस चोरी के बाद दुनिया के सबसे ज्यादा देखे जाने वाले म्यूज़ियमों में शामिल लूव्र ने अपने निदेशक को बदल दिया और सुरक्षा तथा निगरानी व्यवस्था को और मजबूत किया।

मोना लिसा की चोरी ने बढ़ाई पेंटिंग की शोहरत : लूव्र में चोरी और डकैती की कोशिशों का एक लंबा इतिहास रहा है। इसकी सबसे मशहूर घटना 1911 में हुई, जब लियोनार्डो दा विंची की 'मोना लिसा' अपने फ्रेम से गायब हो गई थी। इसे म्यूजियम के पूर्व कर्मचारी विन्सेन्ज़ो पेरुगिया ने चुराया था। वह म्यूज़ियम के अंदर छिपा रहा और बाद में अपने कोट के नीचे पेंटिंग छिपाकर बाहर निकल गया।

दो साल बाद फ्लोरेंस में मिली मोना लिसा : चोरी के करीब दो साल बाद 'मोना लिसा' को इटली के फ्लोरेंस में बरामद किया गया। इस घटना ने लियोनार्डो दा विंची की इस पेंटिंग को दुनिया की सबसे चर्चित और मशहूर कलाकृतियों में शामिल करने में बड़ी भूमिका निभाई।

बोस्टन के इसाबेला स्टीवर्ट गार्डनर म्यूज़ियम की चोरी आज भी रहस्य : इसे अमेरिका के इतिहास की सबसे बड़ी कला चोरियों में से एक माना जाता है। हालांकि, 35 साल बीत जाने के बाद भी बोस्टन के इसाबेला स्टीवर्ट गार्डनर म्यूजियम से चोरी हुई 13 कलाकृतियों का मामला अब तक अनसुलझा है।

पुलिस अधिकारियों के भेष में म्यूजियम में घुसे थे चोर : 18 मार्च 1990 की सुबह दो लोग बोस्टन पुलिस अधिकारियों के भेष में म्यूज़ियम में दाखिल हुए। उन्होंने कहा कि वे एक कॉल का जवाब देने आए हैं। म्यूजियम के अंदर पहुंचने के बाद उन्होंने दो सुरक्षा गार्डों को काबू में कर लिया और उन्हें डक्ट टेप से बांध दिया। इसके बाद करीब 81 मिनट तक उन्होंने म्यूज़ियम से 13 कलाकृतियां चुरा लीं। चोरी हुई कलाकृतियों में रेम्ब्रांट, वर्मीर, डेगास और मैनेट जैसे महान कलाकारों की बेशकीमती कृतियां शामिल थीं। अधिकारियों का कहना है कि चोरी हुई इन कलाकृतियों की कीमत करीब आधा बिलियन डॉलर तक हो सकती है। हालांकि, म्यूज़ियम अधिकारियों के मुताबिक इनका असली मूल्य सिर्फ पैसों में नहीं आंका जा सकता, क्योंकि इनकी जगह दूसरी कलाकृतियां नहीं रखी जा सकतीं। कुछ कलाकृतियों को उनके फ्रेम से काटकर निकाला गया था। इनमें रेम्ब्रांट की मशहूर पेंटिंग 'स्टॉर्म ऑन द सी ऑफ़ गैलिली' भी शामिल थी।

अमेरिका ने ईरान के पांच तेल टैंकर उड़ाए: जवाब में तेहरान ने जॉर्डन पर दागीं मिसाइलें; क्या फिर बढ़ेगा तनाव

वाशिंगटन, एजेंसी। अमेरिका और ईरान के बीच छह महीने से ज्यादा समय से युद्ध चल रहा है। मंगलवार को तनाव फिर बढ़ गया। अमेरिकी सेना ने ईरान के पांच तेल टैंकरों को तबाह कर दिया। अमेरिकी सेंट्रल कमांड के मुताबिक, ईरान के रिवोल्यूशनरी गार्ड्स ने पिछले दो दिनों में अमेरिकी नौसैनिक जहाज को दो बार बैलिस्टिक मिसाइलों से निशाना बनाने की कोशिश की थी।

अमेरिकी युद्धपोत दोनों हमलों से बच गया और गश्त जारी रखी। इन हमलों में कोई अमेरिकी सैनिक घायल नहीं हुआ। इसके जवाब में अमेरिका ने पांच टैंकरों को निशाना बनाया। किविक, चार्मिनार, होराइजन-1 और रिस्को टैंकर गल्फ ऑफ ओमान में थे। पांचवां जहाज डेर्या स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में खर्ग द्वीप के पास था। अमेरिका ने इन्हीं जहाजों को निशाना बनाया है।

ईरान ने अमेरिका को कैसे दिया जवाब : अमेरिकी हमले के बाद ईरान ने भी पलटवार किया। ईरानी सरकारी मीडिया के मुताबिक, उसने जॉर्डन में अमेरिकी ठिकानों की ओर मिसाइलें दागीं। जॉर्डन अमेरिकी सहयोगी है और वहां अमेरिकी सैनिक भी तैनात हैं। जॉर्डन की सेना ने बताया कि उसकी वायु रक्षा प्रणाली ने 18 बैलिस्टिक मिसाइलों को हवा में ही रोक दिया। दो अन्य मिसाइलें ऐसे इलाकों में गिरीं, जहां कोई आबादी नहीं थी। जॉर्डन ने किसी के हताहत होने की सूचना नहीं दी है। वहीं, ईरानी रिवोल्यूशनरी गार्ड्स ने कुवैत और बहरीन के पास मौजूद तेल टैंकरों को तुरंत हटने को कहा है। इतना ही नहीं, ईरान ने दोनों देशों पर अमेरिकी सेना को ठिकाने देने और हमलों में मदद करने का आरोप लगाया। आईआरजीसी ने एक बयान में कहा कि उसने अल-अजराक एयर बेस में अमेरिकी सेना के एफ-35, एफ-16 और एफ-15 लड़ाकू विमानों की मरम्मत, रखरखाव, तैयारी और तैनाती के लिए इस्तेमाल होने वाले एक हैंगर को निशाना बनाया। इसके अलावा, अमेरिकी लड़ाकू विमानों के लिए बने एक शेल्टर पर भी हमला किया गया। आईआरजीसी ने दावा किया कि इस हमले में 'दुश्मन को भारी नुकसान पहुंचाया गया।'

सिन्हुआ समाचार एजेंसी की रिपोर्ट के अनुसार, जॉर्डन की सेना ने बुधवार को कहा कि उसके वायु रक्षा सिस्टम ने ईरान की ओर से दागी गई 20 में से 18 बैलिस्टिक मिसाइलों को नष्ट कर दिया। सेना के अनुसार, बाकी दो मिसाइलें सुनसान इलाकों में गिरीं और किसी तरह के जानमाल के नुकसान की कोई सूचना नहीं है। अमेरिका और ईरान के बीच संघर्ष का सबसे बड़ा आर्थिक मोर्चा स्ट्रेट ऑफ होर्मुज बन गया है। युद्ध शुरू होने से पहले दुनिया के करीब पांचवें हिस्से का तेल इसी रास्ते से गुजरता था। अमेरिका ने ईरानी बंदरगाहों की नाकेबंदी कर रखी है।

हालात: ट्रंप ने 10 घंटे तक एआई तस्वीरों की बौछार की; ईरान की तबाही और अरबों कमाने का दावा

वाशिंगटन, एजेंसी। अगर तस्वीरों में किसी देश, जलडमरूमध्य, झील और यहां तक कि चांद पर भी अमेरिका का दावा किया जा सकता है तो ट्रंप की एआई दुनिया में ऐसा ही हो रहा है।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रविवार को ट्रुथ सोशल पर करीब 10 घंटे तक दर्जनों एआई-निर्मित तस्वीरें पोस्ट कीं, जिनमें होर्मुज जलडमरूमध्य को नया अमेरिकी क्षेत्र, चांद को हमारा और लेक ओंटारियो को लेक अमेरिका दिखाया गया। इन तस्वीरों के बीच ट्रंप ने ईरान को तबाह होता दिखाया और खुद को अमेरिका के सुपरहीरो के रूप में पेश किया। इसी दौरान उन्होंने यह दावा भी किया कि शेयरों और अन्य होल्डिंग्स से उन्होंने अमेरिका के लिए सैकड़ों अरब डॉलर कमाए हैं। इस दावे के समर्थन में हालांकि कोई विस्तृत आंकड़ा या प्रमाण नहीं दिया गया।

ट्रंप ने एक एआई तस्वीर में खुद को व्हाइट हाउस में कई स्क्रीन के सामने शेयर बाजार पर नजर रखते दिखाया। तस्वीर पर संदेश था कि वह यह काम अपने लिए नहीं, बल्कि अमेरिका के लिए करते हैं और शेयरों तथा दूसरी होल्डिंग्स से देश के लिए सैकड़ों अरब डॉलर कमाए हैं। ट्रंप की यह पोस्ट ऐसे समय हुई है जब उनकी सोशल मीडिया कंपनी ट्रंप मीडिया की ट्रुथ एपीआई सेवा को लेकर सवाल उठ रहे हैं। जुलाई में अमेरिकी सीनेटरों ने सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन से इस सेवा की जांच करने का आग्रह किया था।ट्रंप की पोस्ट का बड़ा हिस्सा ईरान पर केंद्रित रहा। एक तस्वीर में वह युद्धपोत के डेक से कई विस्फोटों को देखते नजर आए, जबकि दूसरी में अमेरिकी झंडे की थीम वाले हथौड़े से ईरान के नक्शे पर वार करते दिखे। एक अन्य तस्वीर में खार्ग द्वीप पर उड़ता लड़ाकू विमान दिखाया गया, जिस पर लिखा था 'बाय बाय, खार्ग।'ईरान की अर्थव्यवस्था को लेकर भी ट्रंप ने कई चार्ट साझा किए। ट्रंप ने एआई तस्वीरों के जरिए अपनी राजनीतिक छवि को भी नए अंदाज में पेश किया। कुछ तस्वीरों में वह भविष्य के रोबोटों से घिरे नेता के रूप में दिखे, पीछे अमेरिकी कैपिटल था।

बेंजामिन नेतन्याहू का 24 घंटे का यूएन दौरा: ममदानी ने की थी गिरफ्तारी की मांग, फिर क्यों जा रहे न्यूयॉर्क

संयुक्त राष्ट्र, एजेंसी। नेतन्याहू संयुक्त राष्ट्र महासभा में शामिल होने के लिए न्यूयॉर्क जाएंगे। इस्राइल के संयुक्त राष्ट्र राजदूत डैनी डैनन ने मंगलवार को बताया कि नेतन्याहू 23 सितंबर की देर रात न्यूयॉर्क पहुंचेंगे। 24 सितंबर की दोपहर वह संयुक्त राष्ट्र महासभा को संबोधित करेंगे। इसके बाद उसी रात इस्राइल लौट जाएंगे। डैनन ने कहा कि मौजूदा हालात में प्रधानमंत्री का वहां आना जरूरी है और उनके पास इसके अलावा कोई विकल्प नहीं है।

ममदानी ने नेतन्याहू की गिरफ्तारी की मांग क्यों की : न्यूयॉर्क शहर के 112वें मेयर ममदानी ने नेतन्याहू को 'युद्ध अपराधी' बताया था और उनकी गिरफ्तारी की मांग की थी। बाद में उन्हें यह मांग वापस लेनी पड़ी, क्योंकि न्यूयॉर्क शहर के पास नेतन्याहू को गिरफ्तार करने का कानूनी अधिकार नहीं है। ममदानी ने नवंबर 2024 में अंतरराष्ट्रीय अपराध न्यायालय यानी आईसीसी की ओर से जारी गिरफ्तारी वारंट का हवाला दिया था। इस्राइल के राजदूत डैनन ने ममदानी के बयान पर नाराजगी जताई। इस्राइल को निशाना बनाकर राजनीति करना अब आसान तरीका बन गया है। डैनन ने कहा, 'हमारे लिए यह महत्वपूर्ण है कि प्रधानमंत्री आएं। आईसीसी के गिरफ्तारी वारंट में नेतन्याहू पर क्या आरोप हैं अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय (आईसीसी) ने नवंबर 2024 में नेतन्याहू और एक अन्य इस्राइली अधिकारी के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया था। अदालत ने कहा था कि नेतन्याहू पर मानवता के खिलाफ अपराधों के आरोपों को लेकर कार्रवाई का आधार है। वारंट में कहा गया कि गाजा में हमास के खिलाफ अभियान के दौरान मानवीय सहायता रोककर 'भूख को युद्ध के हथियार' के तौर पर इस्तेमाल किया गया।

क्या न्यूयॉर्क पहुंचते ही नेतन्याहू गिरफ्तार हो सकते हैं : न्यूयॉर्क शहर के पास आईसीसी के गिरफ्तारी वारंट को लागू करने का कानूनी अधिकार नहीं है। हालांकि ममदानी ने अमेरिकी संघीय सरकार से नेतन्याहू के खिलाफ कार्रवाई करने की अपील की है। अमेरिका और इस्राइल दोनों आईसीसी के सदस्य नहीं हैं। वहीं ट्रंप प्रशासन ने आईसीसी के कर्मचारियों पर कई प्रतिबंध लगाए हैं और इस न्यायालय को खत्म करने की कोशिश की है।

इस दौरे से जुड़ी सात अहम बातें क्या हैं : दौरा करीब 24 घंटे का होगाः नेतन्याहू 23 सितंबर की देर रात न्यूयॉर्क पहुंचेंगे और 24 सितंबर की दोपहर संयुक्त राष्ट्र महासभा को संबोधित करेंगे। इसके बाद उसी रात इस्राइल वापस लौट जाएंगे। ममदानी ने गिरफ्तारी की मांग की थीः न्यूयॉर्क के मेयर ने नेतन्याहू को 'युद्ध अपराधी' बताया था और उनकी गिरफ्तारी की मांग की थी। हालांकि शहर के पास ऐसा करने का कानूनी अधिकार नहीं है। आईसीसी ने नवंबर 2024 में वारंट जारी कियाः अंतरराष्ट्रीय अपराध न्यायालय ने नेतन्याहू के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया था। इसमें गाजा युद्ध के दौरान मानवीय सहायता रोकने और नागरिकों को निशाना बनाने के आरोप शामिल हैं।

यूक्रेन को 2024 में हुआ 1.2 अरब डॉलर का नुकसान, रक्षा सौदों में जमकर हो रहा भ्रष्टाचार; कैसे हुआ खेल

कीव/अल्बानी, एजेंसी। रूसी सैनिकों ने 2024 में पूर्वी यूक्रेन में खाइयों पर हमला बोला तो यूक्रेनी तोपखाने के जवानों ने गोलीबारी शुरू कर दी। लेकिन गोले आगे बढ़ने वाली सेना के पास फटने के बजाय, लॉन्च ट्यूब से बाहर गिर गए या हल्की-सी आवाज के साथ जमीन पर जा गिरे, जिससे धूल का गुबार उड़ने लगा।

यह यूक्रेन की रक्षा कंपनियों की गद्दारी का नतीजा था। दरअसल, रक्षा कंपनियां भ्रष्टाचार में शामिल थी और उन्होंने सेना को हजारों खराब मोर्टार गोलों की आपूर्ति की थी। गोपनीय सैन्य ऑडिट रिपोर्ट सामने आने पर पता चला है कि अकेले 2024 में यूक्रेन को धोखाधड़ी और बर्बादी के कारण 1.2

अरब डॉलर का नुकसान हुआ। सैन्य खरीद पर स्टेट ऑडिट सर्विस व रक्षा मंत्रालय की गोपनीय ऑडिट रिपोर्ट के अनुसार, यूक्रेन के शीर्ष 10 सैन्य ठेकेदारों में से सात ऐसे थे जिन्होंने नए अनुबंध हासिल किए, जबकि उनके खिलाफ धोखाधड़ी के खुले आपराधिक मामले चल रहे थे। भ्रष्टाचार का खुलासा होने पर कुछ कंपनियों के सीईओ या शीर्ष अधिकारियों की गिरफ्तारी के बावजूद इन कंपनियों को ब्लैकलिस्ट करने या इनसे दूरी बनाने के बजाय सरकारी एजेंसियां आंख मूंदकर इन्हें उपकृत करती रहीं।

भ्रष्टाचार के मामले में जमानत, फिर भी सौदा : सरकारी स्वामित्व वाले एक यूक्रेनी कारखाने ने सेना को 233,000 दोषपूर्ण मोर्टार सौंपे। कारखाने के निदेशक लियोनिद शाइमैन को युद्ध के दौरान रक्षा उद्योग में सबसे बड़े घोटालों में से एक में गिरफ्तार किया गया था। चौंकाने वाली बात यह है कि जब शाइमैन को लगभग 28 करोड़ डॉलर का पहला मोर्टार अनुबंध दिया गया था, तब वह पहले से ही भ्रष्टाचार के मामलों में जमानत पर बाहर थे।

बिचौलियों का खेल, कम बोली की अनदेखी : जब रक्षा खरीद एजेंसी ने सैकड़ों मिलियन डॉलर के रॉकेट आर्टिलरी खरीदने के लिए बोलियां मंगाईं, तो तीन कंपनियों ने जवाब दिया। तुर्की की मूल निर्माता कंपनी आर्का डिफेंस ने सीधे कारखाने से सबसे कम बोली (4,200 डॉलर प्रति रॉकेट) लगाई। अनुबंध सबसे ऊंची बोली लगाने वाली कंपनी चेकोस्लोवाक ग्रुप की सहायक कंपनी को दे दिया गया। रक्षा अनुबंधों ने चेक समूह के 33 वर्षीय मालिक मिचेल स्ट्रनाड को फोर्ब्स की सूची में सबसे अमीर हथियार निर्माता के रूप में स्थापित कर दिया।

ट्रेड वॉर में ट्रंप की नई चाल: कनाडा के डेयरी-शराब और बाइक अमेरिका में बैन, अब क्या पलटवार करेंगे कार्नी

वाशिंगटन,एजेंसी। अमेरिका कनाडा से आने वाले डेयरी प्रोडक्ट्स, ज्यादातर शराब और मोटरसाइकिलों पर रोक लगाने जा रहा है। व्हाइट हाउस ने मंगलवार को इसकी घोषणा की। यह कदम दोनों देशों के बीच लगातार बढ़ते ट्रेड वॉर के बीच उठाया गया है। यह रोक तीन हफ्ते में लागू होगी। इससे पहले मंगलवार को ही कनाडा ने अमेरिका से होने वाले 20 अरब डॉलर के आयात पर जवाबी टैरिफ लगा दिए थे।

कनाडाई सामानों को सरकारी कॉन्ट्रैक्ट से बाहर रखने का फैसला : मंगलवार को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कनाडा के प्रोडक्ट्स को अमेरिकी सरकार के बड़े और लंबे समय वाले कॉन्ट्रैक्ट्स से बाहर रखने का फैसला किया। यह कदम कनाडा के जवाबी टैरिफ लागू करने और प्रधानमंत्री मार्क कार्नी के अमेरिका पर देश की निर्भरता कम करने की कोशिशों को तेज करने के वादे के बाद उठाया गया है।

ट्रंप ने त्रस्र को दिए निर्देश : ट्रंप ने अमेरिकी जनरल सर्विसेज एडमिनिस्ट्रेशन (त्रस्र) को निर्देश दिया है कि वह कनाडा के प्रोडक्ट्स को सरकारी कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए अयोग्य घोषित करे। हालांकि, यह रोक तब तक जारी रहेगी जब तक कनाडा अमेरिकी प्रोडक्ट्स के लिए 'पूरी और निष्पक्ष बराबरी' की अनुमति नहीं देता।

'कनाडा को ज्यादा आत्मनिर्भर बनना होगा' : इससे पहले मंगलवार को कनाडाई प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने कहा कि कनाडा की रणनीति अब ज्यादा स्वतंत्र और आत्मनिर्भर बनने की है। उन्होंने कहा कि इसका मकसद यह सुनिश्चित करना है कि कोई भी देश हमें बंधक न बना सके और हम

अपनी मर्जी से जी सकें।

यूरोपीय संघ के साथ रिश्ते मजबूत करने की तैयारी : एक कनाडाई अधिकारी ने नाम न बताने की शर्त पर बताया कि कनाडा यूरोपियन यूनियन (श्व) के साथ ऐसे रिश्ते बनाने पर विचार कर रहा है, जो पूरी सदस्यता तो न हों, लेकिन उसके काफी करीब हों। इन विकल्पों में मौजूदा समझौतों का विस्तार करना, नई संधि पर बातचीत करना या सहयोग के दूसरे रास्ते तलाशना शामिल हो सकता है। अधिकारी ने कहा कि कनाडा पहले से ही प्रांतों, क्षेत्रों और लेबर ग्रुप्स से सलाह-मशविरा कर रहा है कि श्व के साथ किस तरह के गहरे संबंध बनाए जा सकते हैं। हालांकि, अभी तक किसी एक मॉडल पर फैसला नहीं हुआ है। कार्नी अगले हफ्ते फ्रांस के स्ट्रासबर्ग जाने वाले हैं। वहां वह 16 सितंबर को यूरोपियन कमीशन की प्रेसिडेंट उर्सुला वॉन डेर लेयेन के 'स्टेट ऑफ द यूरोपियन यूनियन' भाषण में शामिल होंगे।

दशकों पुराने करीबी रिश्ते में बढ़ी दरार : अमेरिका और कनाडा के बीच पैदा हुई यह दरार दुनिया के सबसे करीबी रिश्तों में से एक को पूरी तरह बदल रही है। दोनों देशों की अर्थव्यवस्थाएं एक-दूसरे से गहराई से जुड़ी हुई हैं और उनके बीच रक्षा एवं सुरक्षा के भी बेहद करीबी संबंध हैं। इसके बावजूद ट्रंप ने अपने पहले कार्यकाल के दौरान नॉर्थ अमेरिकन ट्रेड एग्रीमेंट पर दोबारा बातचीत की थी और बाद में उसकी कई बार तारीफ भी की, लेकिन अब उनके प्रशासन ने कनाडाई सामानों पर कई टैरिफ लगा दिए हैं।

यूके छोड़ने पर कानूनी रोक': विजय माल्या बोले- मैं भगोड़ा नहीं; भारत सरकार पर लगाए गंभीर आरोप, क्या है मामला

लंदन, एजेंसी। शराब कारोबारी विजय माल्या ने एक बार फिर खुद को 'भगोड़ा' कहे जाने पर सवाल उठाया है। माल्या ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कहा कि मैं भारत लौटने से भाग नहीं रहा हूं। मुझे भगोड़ा कहने वालों को समझना चाहिए कि मैं 1992 से यूके यानी ब्रिटेन का स्थायी निवासी हूं। फिलहाल कानूनी तौर पर देश छोड़ने पर रोक है। भारत सरकार ने मेरे साथ घोर अन्याय किया।

भारत में माल्या को भगोड़ा क्यों कहा जाता है : भारत सरकार के रिकॉर्ड में विजय माल्या को भगोड़ा आर्थिक अपराधी घोषित किया जा चुका है। अक्टूबर 2025 में वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने लोकसभा में बताया था कि भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम, 2018 के तहत 15 लोगों को भगोड़ा आर्थिक अपराधी घोषित किया गया है। इस सूची में विजय माल्या और नीरव मोदी समेत कई चर्चित नाम शामिल हैं।

यही वजह है कि भारत में माल्या को भगोड़ा आर्थिक अपराधी के तौर पर देखा जाता है। हालांकि, माल्या अब इसी पहचान पर सवाल उठा रहे हैं। उनका कहना है कि ब्रिटेन में उनका रहना किसी तरह भारत से भागने की कोशिश नहीं है, बल्कि उनके खिलाफ चल रही कानूनी स्थिति का नतीजा है।

भारत सरकार माल्या की वापसी पर क्या कह चुकी है : भारत सरकार का रुख इस मामले में पहले से साफ रहा है। दिसंबर 2025 में विदेश मंत्रालय ने कहा था कि भारत में कानून के तहत वांछित लोगों को देश वापस लाने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। मंत्रालय ने माना था कि ऐसे मामलों में कई कानूनी प्रक्रियाएं शामिल होती हैं। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा था कि सरकार इस मामले में कई देशों के साथ बातचीत कर रही है और प्रक्रिया जारी है। उनका कहना था कि सरकार की कोशिश है कि आर्थिक अपराध के मामलों में वांछित लोग भारत लौटें और यहां की अदालतों में मुकदमे का सामना करें। माल्या ने 14,131 करोड़ रुपये की वसूली का दावा क्यों किया विजय माल्या ने मंगलवार को एक और पोस्ट किया

था। इसमें उन्होंने बॉम्बे हाईकोर्ट में प्रवर्तन निदेशालय की ओर से दाखिल एक कथित हलफनामे का हवाला दिया। माल्या का दावा है कि इस हलफनामे के एक हिस्से में 2021 में उनसे 14,131.60 करोड़ रुपये की वसूली का जिक्र है। माल्या ने सवाल उठाया कि अगर उनसे इतनी बड़ी रकम वसूल की जा चुकी है, तो उन्हें अब भी बैंक धोखाधड़ी के आरोपी के तौर पर क्यों पेश किया जाता है। उन्होंने एक स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट की तालिका भी साझा की। इसके जरिए उन्होंने कहा कि अब सवाल यह होना चाहिए कि उन्हें उनकी रकम वापस कब मिलेगी। विजय माल्या ने यह भी दावा किया कि ईडी ने उनके अटैच फंड से 350 करोड़ रुपये से ज्यादा रकम किंगफिशर कर्मचारियों को भुगतान करने के लिए जारी की थी। उनका कहना है कि उनकी संपत्तियां और फंड अटैच होने के कारण वह खुद कर्मचारियों का भुगतान नहीं कर सके।

माल्या के मामले में अदालत का रुख क्या : विजय माल्या के मामले में बॉम्बे हाईकोर्ट भी सख्त रुख अपना चुका है। फरवरी 2026 में अदालत ने उन्हें फटकार लगाते हुए कहा था कि वह जानबूझकर अदालती कार्यवाही से बच रहे हैं। अदालत ने कहा था कि ऐसी स्थिति में वह समानता के आधार पर राहत की मांग नहीं कर सकते। उच्च अदालत ने माल्या को यह स्पष्ट करने का अंतिम मौका भी दिया था कि क्या वह भारत लौटने का इरादा रखते हैं। माल्या की याचिका भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम की सांविधानिक वैधता और उन्हें भगोड़ा घोषित करने की कार्रवाई को चुनौती देती है। मुख्य न्यायाधीश चंद्रशेखर की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा था कि वह यह दर्ज करने के पक्ष में है कि माल्या अदालत के अधिकार क्षेत्र से बच रहे हैं। ऐसे में वह अपनी याचिका में राहत की उम्मीद नहीं कर सकते। माल्या का दावा है कि वह 1992 से ब्रिटेन के स्थायी निवासी हैं और फिलहाल कानूनी तौर पर ब्रिटेन छोड़ने पर रोक है। अक्टूबर 2025 में सरकार ने लोकसभा में बताया था कि 15 लोगों को भगोड़ा आर्थिक अपराधी घोषित किया गया है, जिनमें माल्या और नीरव मोदी शामिल हैं। दिसंबर 2025 में विदेश मंत्रालय ने कहा था कि भारत वांछित आर्थिक अपराधियों को वापस लाने के लिए अलग-अलग देशों के साथ कानूनी प्रक्रिया आगे बढ़ा रहा है।

माल्या ने ईडी के कथित हलफनामे का हवाला देते हुए 2021 तक 14,131.60 करोड़ रुपये की वसूली का दावा किया है।

स्वामी,मुद्रक व् प्रकाशकः सुरेश मौर्या द्वारा अष्ठ विनायक ओफ़सेट एफपी,149 प्लोट 26 खोडीयारनगर,सिद्धिविनायक मंदीर के पास ,भाटेना) हो.सो अंजना सुरत गुजरात से मुद्रित एवं 191 महादेव नगर उधना सुरत गुजरात से प्रकाशित संपादक : सुरेश मौया (M) 9879141480 RNI No.:GUJHIN/2018/75100 (Subject to Surat jurisdiction)

Web site : www.krantisamay.com & epaper.krantisamay.com www.facebook.com/krantisamay1 www.twitter.com/krantisamay1

महिला के पेट से 14 पेन, 5 लकड़ी के चम्मच और मोमबत्ती निकाली, डॉक्टर हैरान

नरसाराओपेट (एजेंसी)। आंध्र प्रदेश के पलनाडु जिले से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है। महिला को सीने में तेज दर्द की शिकायत के बाद अस्पताल ले जाया गया। जांच के दौरान डॉक्टरों को उसके पेट के अंदर कई असामान्य वस्तुएं मौजूद होने का पता चला। सर्जरी के दौरान महिला के पेट से 14 पेन, 5 लकड़ी के चम्मच और एक मोमबत्ती निकाली गई। जानकारी के मुताबिक पेटलुरिवारीपलेनी मंडल की रहने वाली महिला को कुछ समय से सीने में दर्द की शिकायत थी। दर्द बढ़ने पर परिजन उसे निजी अस्पताल लेकर पहुंचे। डॉक्टरों ने जांच के बाद कई मेडिकल टेस्ट और स्कैन कराए। रिपोर्ट में पेट के अंदर ठोस वस्तुओं की मौजूदगी सामने आई। मामले की गंभीरता को देखते हुए डॉक्टरों ने महिला की सर्जरी करने का फैसला लिया। लैप्रोस्कोपिक तकनीक की मदद से पेट में छोटा चीरा लगाकर अंदर मौजूद वस्तुओं को एक-एक कर बाहर निकाला। डॉक्टरों के मुताबिक पेट से 14 पेन, 5 लकड़ी के चम्मच और एक मोमबत्ती निकाली गई। डॉक्टरों ने बताया कि एक पेन का ढक्कन नहीं था और उसका हिस्सा पेट की अंदरूनी सतह में चुभ रहा था। माना जा रहा है कि इसी वजह से महिला को दर्द हो रहा था। डॉक्टरों के मुताबिक एक साथ इतनी संख्या में ठोस वस्तुओं का पेट में पाया जाना बेहद असामान्य और दुर्लभ है।

बीजेपी कर सकती है 5 राज्यों में चुनाव से पहले नए प्रभारियों की घोषणा

नई दिल्ली, (एजेंसी)। भारतीय जनता पार्टी ने आगामी विधानसभा चुनावों से ठीक पहले नए मोर्चा प्रभारियों के नामों की घोषणा कर सकती है। सूत्रों के मुताबिक हरिश द्विवेदी को युवा मोर्चा का प्रभारी बनाया जा सकता है। वहीं सतीश पूनिया को भी पद मिल सकता है। पार्टी महिला मोर्चा, एसएसटी, ओबीसी और किसान मोर्चा के प्रभारियों की भी घोषणा कर सकती है। बीजेपी हरीश दिवेदी को युवा मोर्चा का प्रभारी बना सकती है, वहीं महिला मोर्चा की डी. पुरंदेश्वरी को प्रभारी, एससी मोर्चा के संजय भाटिया, ओबीसी मोर्चा वैजयंत पांडा, किसान मोर्चा लाल सिंह आर्या, एसटी मोर्चा सतीश पूनिया, अल्पसंख्यक मोर्चा गजेंद्र पटेल को जिम्मेदारी सौप सकती है।

मणिपुर में प्रतिबंधित संगठनों के चार उग्रवादी गिरफ्तार, पुलिस कर रही पूछताछ

इंफाल (एजेंसी)। मणिपुर के दो घाटी जिलों से सुरक्षा बलों ने प्रतिबंधित संगठनों से जुड़े चार उग्रवादियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने गुरुवार को बताया कि ये सभी गिरफ्तारियां बुधवार को की गईं। पुलिस ने बताया कि असम राइफल्स और गढ़वाल राइफल्स को मिली खुफिया जानकारी के आधार पर मणिपुर के इंफाल पूर्व जिले के माना इंगखोल में 'नेशनल रिवोल्यूशनरी फ्रंट ऑफ मणिपुर' के 28 साल के सक्रिय सदस्य को पकड़ा। उन्होंने बताया कि इंफाल पश्चिम जिले में चिंगमेइरोंग से प्रतिबंधित कांगलीपाक कम्युनिस्ट पार्टी के 44 साल एक सदस्य को गिरफ्तार किया गया है। अधिकारी के मुताबिक पकड़े गए दो अन्य लोगों में एक प्रतिबंधित कांगलेई याओल कन्ना लुप का सक्रिय सदस्य है, जिसे इंफाल पश्चिम के सागोलटोंगबा स्थित उसके घर से पकड़ा। वहीं, दूसरा व्यक्ति इंफाल पूर्व के अहल्लुप से पकड़ा गया, जो केसीपी का सदस्य है। गिरफ्तार किए गए उग्रवादियों से पूछताछ की जा रही है और मामले की जांच जारी है।

सलमान की काला हिरण पर रोक की मांग : फिल्म रिलीज को तैयार नहीं

मुंबई (एजेंसी)। अभिनेता सलमान खान की याचिका पर काला हिरण- द बैटल फॉर लिगेसी फिल्म को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट में कानूनी लड़ाई जारी है। सलमान ने अपनी पहचान और 1998 के काले हिरण मामले के इस्तेमाल का आरोप लगाकर फिल्म की रिलीज और प्रचार पर रोक लगाने की मांग की है। मामले की सुनवाई के दौरान, फिल्म निर्माताओं ने अदालत को बताया कि फिल्म अभी रिलीज के लिए तैयार नहीं है और केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड (सीबीएफसी) से प्रमाणित होना बाकी है। सलमान का आरोप है कि फिल्म में उनके जीवन से जुड़े तथ्यों और विवादों का अनधिकृत इस्तेमाल किया जा रहा है। फिल्म के पोस्टर और टीजर में एक ऐसा किरदार दिखाया गया है जो उनसे काफी मिलता-जुलता है, यहाँ तक कि उनके प्रसिद्ध ब्रेसलेट का इस्तेमाल हुआ है। सलमान का कहना है कि यह उनकी पर्सनैलिटी राइट्स का उल्लंघन है और इससे उनकी छवि को नुकसान होता है। वहीं, फिल्म के निर्माता और निर्देशक इन आरोपों को खारिज कर रहे हैं। उनका कहना है कि फिल्म काल्पनिक है, किरदार का नाम अयान खान है और कोई भी प्रोस्थेटिक मेकअप सलमान जैसा दिखने के लिए इस्तेमाल नहीं किया गया। ब्रेसलेट को लेकर भी उनका तर्क है कि यह सिर्फ सलमान ही नहीं पहनते। हालांकि, सलमान के वकील ने कोर्ट में ओटीटी प्लेटफॉर्म पर फिल्म रिलीज की संभावना को देखकर , सेंसर बोर्ड प्रमाणन की अनुपस्थिति में भी रोक लगाने की मांग की, जिसे कोर्ट ने अपने आदेश में शामिल किया। अदालत ने फिल्म निर्माताओं को दो सप्ताह के भीतरजवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है, और मामले की अगली सुनवाई 30 सितंबर को निर्धारित की गई है।

सुप्रीम कोर्ट का सवाल- पति पर रेप का केस कैसे चलाया जा सकता है?

वैवाहिक बलात्कार अपवाद की संवैधानिक वैधता पर तीन हफ्ते बाद अंतिम सुनवाई

नई दिल्ली, एजेंसी।
वैवाहिक बलात्कार (मैरिटल रेप) को लेकर सुप्रीम कोर्ट में चल रही संवैधानिक चुनौती पर बुधवार को सुनवाई हुई। चीफ जस्टिस सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय पीठ ने मामले की अंतिम सुनवाई तीन सप्ताह बाद सूचीबद्ध करने का निर्देश दिया। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने सवाल उठाया कि जब कानून में वैवाहिक बलात्कार का अपवाद मौजूद है, तो पत्नी के साथ बलात्कार के आरोप में पति के खिलाफ अभियोजन किस आधार पर चलाया जा सकता है।

पीठ ने पूछा कि जब तक वैवाहिक बलात्कार अपवाद की संवैधानिक वैधता पर सुप्रीम कोर्ट फैसला नहीं कर देता, तब तक पत्नी से बलात्कार के आरोप में पति के खिलाफ मुकदमा कैसे चल सकता है? जस्टिस जॉयमाल्या बागची ने भी इसी पहलू पर सवाल उठाते हुए कहा कि यदि आईपीसी की धारा 375 में स्पष्ट रूप से वैवाहिक बलात्कार का अपवाद था, तो उसकी संवैधानिक वैधता पर फैसला होने तक अभियोजन की अनुमति दी जा सकती है या नहीं।

पीड़ितों की सुरक्षा पर भी कोर्ट का जोर

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वह पीड़ितों की सुरक्षा सुनिश्चित करेगा, लेकिन मौजूदा कानूनी प्रावधानों के रहते अभियोजन के अधिकार का सवाल भी महत्वपूर्ण है। यह मामला कर्नाटक हाईकोर्ट के उस फैसले से जुड़ा है, जिसमें कहा गया था कि वैवाहिक बलात्कार के मामले में पति को कानून के तहत पूर्ण छूट हासिल नहीं है। हाईकोर्ट ने पत्नी की इच्छा के खिलाफ यौन संबंध बनाने पर पति के खिलाफ बलात्कार का मुकदमा चलाने की अनुमति दी थी।

बीएनएस में भी वैवाहिक बलात्कार का अपवाद

मामला मूल रूप से आईपीसी की धारा 375 के अपवाद-2 से जुड़ा है। अब आईपीसी की जगह भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस), 2023 लागू है। बीएनएस में भी 18 वर्ष या उससे अधिक उम्र की पत्नी के साथ पति के यौन संबंध को लेकर समान अपवाद मौजूद है। सुप्रीम कोर्ट ने संकेत दिया कि अंतिम सुनवाई में दो प्रमुख सवालों पर विचार होगा। पहला, यदि वैवाहिक बलात्कार का अपवाद बरकरार रहता है तो क्या पति के खिलाफ अभियोजन जारी रखा जा सकता है। दूसरा, क्या यह अपवाद संविधान की कसौटी पर कायम रह सकता है।

केंद्र ने अपराध बनाने का किया था विरोध

केंद्र सरकार ने 2024 में दाखिल हलफनामे में वैवाहिक बलात्कार को अपराध बनाने का विरोध किया था। केंद्र का कहना था कि विवाहित महिलाओं को यौन हिंसा से बचाने के लिए मौजूदा कानूनों में पर्याप्त वैकल्पिक उपाय मौजूद हैं। सरकार के अनुसार विवाह संस्था के भीतर बलात्कार का अपराध लागू करना अत्यधिक कठोर और असंगत हो सकता है तथा यह मुख्य रूप से सामाजिक और विधायी नीति का विषय है।

कॉकरोच जनता पार्टी के नेता मानहानि मामले में तलब, बीजेपी प्रवक्ता भाटिया ने मांगा हर्जाना

नई दिल्ली (एजेंसी)। दिल्ली हाईकोर्ट ने भाजपा नेता और वरिष्ठ अधिवक्ता गौरव भाटिया द्वारा दायर 2 करोड़ रुपये के मानहानि के मुकदमे में कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) के तीन नेताओं अभिजीत दीपके, सौरव दास और आशुतोष रांका को अदालत तलब किया है। अदालत ने सीजेपी को समन जारी किया है। यह मामला भाटिया के खिलाफ आपत्तिजनक और बिना सत्यापन के पोस्ट करने से जुड़ा है। न्यायमूर्ति तुषार राव गेडेला की पीठ ने मौखिक रूप से कहा कि सीजेपी नेताओं सौरव दास और आशुतोष रांका द्वारा भाटिया के बारे में बिना सत्यापन के किए पोस्ट अनुचित थे। अदालत ने उन्हें ये पोस्ट स्वयं हटाने का सुझाव दिया था, जिसके बाद उनके वकीलों ने कुछ पोस्ट हटाने की पुष्टि की और अन्य को भी हटाने का आश्वासन दिया। वहीं, दीपके ने अपना बचाव कर कहा कि उन्होंने इस मुद्दे पर कुछ नहीं लिखा था। मामले की सुनवाई के दौरान भाटिया ने मध्यस्थता के लिए अदालत की पेशकश को अस्वीकार कर अपनी प्रतिष्ठा को पहुंची क्षति के लिए हर्जाना पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि सीजेपी नेताओं के सोशल मीडिया पर लाखों फॉलोअर्स हैं और उनके पोस्ट एक दिन में 10 लाख से अधिक लोगों तक पहुंचते हैं, जिससे हुई क्षति गंभीर है। बीजेपी प्रवक्ता भाटिया की मांग पर अदालत ने सभी आपत्तिजनक पोस्ट को 24 घंटे के भीतर हटाने का आदेश दिया और एक्स तथा मेटा को निर्देश दिया कि भविष्य में ये पोस्ट प्लेटफॉर्म पर फिर न दिखें। इसके साथ ही अदालत ने सीजेपी और उसके नेताओं को समन जारी किया। अदालत ने सीजेपी नेताओं को सलाह दी कि वे कुछ भी साझा करने से पहले तथ्यों की पुष्टि करें। न्यायालय ने कहा कि विरोध करने के कई वैध तरीके हैं और युवाओं को इस हद तक जाने की आवश्यकता नहीं है।

प्रियंका गांधी का नाम और आवाज इस्तेमाल कर लोगों को ठगने की कोशिश

-कार्यालय ने जारी किया स्कैम अलर्ट, लोगों से की ऐसे फर्जी निवेश से बचने की अपील

नई दिल्ली, एजेंसी।
सांसद प्रियंका गांधी के नाम और उनकी आवाज का इस्तेमाल कर साइबर ठग लोगों को ठगने की कोशिश कर रहे हैं। इसको लेकर प्रियंका गांधी के कार्यालय ने इंस्टाग्राम पर गुरुवार को स्कैम अलर्ट जारी किया। कार्यालय ने बताया कि वॉट्सऐप, इंस्टाग्राम और अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर प्रियंका गांधी की एआई से बनी फर्जी फोटो और आवाज वाले वीडियो वायरल हो रहे हैं। इन वीडियो में लोगों से पैसे निवेश करने को कहा जा रहा है।
मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक कार्यालय ने साफ कहा है कि ये सभी वीडियो स्कैम हैं। लोगों से अपील की गई है कि ऐसे किसी भी लिंक पर क्लिक न करें और न ही निवेश करें। ऐसे पोस्ट को रिपोर्ट और ब्लॉक करें। इससे पहले अगस्त महीने में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के नाम पर भी ऐसा ही फर्जी वीडियो सामने आया था, जिसका सरकार ने खंडन किया था। उस वीडियो में दावा किया जा रहा था कि 22 हजार रुपए के शुरुआती निवेश पर हर हफ्ते साढ़े पांच लाख रुपए की कमाई होगी। यह एक निवेश योजना का प्रचार था। फैक्ट चेक यूनिट ने जांच में पाया कि यह वीडियो पूरी तरह फर्जी है और एआई से तैयार किया गया है। आजकल साइबर ठग लोगों का भरोसा जीतने के लिए रोज नए-नए तरीके निकाल रहे हैं। बड़े नेताओं और जानी-मानी हस्तियों की एआई से आवाज और वीडियो बनाकर लोगों को भरोसे में लिया जा रहा है और लाखों-करोड़ों की ठगी की जा रही है।
एक्सपर्ट्स का कहना है कि अगर कोई वीडियो आपको बहुत ज्यादा मुनाफे का लालच दे रहा है, तो सतर्क हो जाएं। किसी भी अनजान लिंक पर क्लिक करने से बचें और किसी भी निवेश योजना में पैसा लगाने से पहले उसकी सच्चाई की जांच जरूर करें। सरकार या किसी नेता की तरफ से ऐसी कोई योजना आती है तो उसकी जानकारी आधिकारिक वेबसाइट पर जरूर देखें।

मुंबई-गोवा हाईवे में देरी पर गडकरी बोले- उद्घाटन में नहीं जाऊंगा

बोले- ठेकेदारों को ब्लैकलिस्ट करने और अधिकारियों को निलंबित करने का रिकॉर्ड बनाऊंगा

पणजी, एजेंसी।
मुंबई-गोवा हाईवे के चौड़ीकरण में हो रही देरी पर केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने नाराजगी जताई है। उन्होंने कहा कि परियोजना में देरी को लेकर उन्हें शर्मिंदगी महसूस होती है। गडकरी ने यह भी कहा कि हाईवे का काम पूरा होने के बाद होने वाले उद्घाटन कार्यक्रम में वह शामिल नहीं होंगे। उन्होंने कहा कि परियोजनाओं में देरी और खराब गुणवत्ता के लिए जिम्मेदार ठेकेदारों को ब्लैकलिस्ट करने और लापरवाही करने वाले अधिकारियों को निलंबित करने का रिकॉर्ड बनाना चाहते हैं।
गडकरी ने बुधवार को पणजी के पास पोरवोरिम में छह लेन वाले एलिवेटेड रोड कॉरिडोर के उद्घाटन के बाद उन्होंने यह बातें कहीं। उन्होंने कहा कि वह अक्टूबर में मुंबई-गोवा हाईवे से होकर गोवा जाएंगे और रास्ते में खुद काम की स्थिति का निरीक्षण करेंगे। उन्होंने बताया कि इस संबंध में 8 सितंबर को अधिकारियों के साथ बैठक भी हुई थी।
गडकरी के मुताबिक करीब 440 किलोमीटर लंबे मुंबई-गोवा हाईवे के चौड़ीकरण का 93-94 प्रतिशत काम पूरा हो चुका है। इसके बावजूद कई हिस्सों में गड्ढे, जलभराव, मरम्मत और ट्रैफिक जाम जैसी समस्याएं बनी हुई हैं। मई में खारपाड़ा टोल प्लाजा पर टोल वसूली भी शुरू हो गई थी, लेकिन परियोजना के कुछ हिस्सों में काम और सुधार जारी है। वर्ष 2021 में बंदरों के लिए बनाया गया एक ओवरपास भी ढह चुका है।

जमीन अधिग्रहण से लेकर ठेकेदारों की समस्या

मुंबई-गोवा हाईवे का चौड़ीकरण पहले 2016 तक पूरा किया जाना था, लेकिन जमीन अधिग्रहण, निर्माण पूर्व मंजूरियों और ठेकेदारों से जुड़ी समस्याओं के कारण परियोजना में लगातार देरी हुई। केंद्र सरकार ने 2024 में संसद में भी बताया था कि जमीन अधिग्रहण और कुछ ठेकेदारों की आर्थिक परेशानियों के कारण काम प्रभावित हुआ। गडकरी ने हाईवे के किनारे वैज्ञानिक तरीके से लैंडस्केपिंग करने की जरूरत पर भी जोर दिया। उन्होंने कहा कि ठेकेदारों की मनमर्जी से पेड़

लगाने के बजाय विशेषज्ञों के अध्ययन के आधार पर फूल और पेड़ों की ऐसी प्रजातियां चुनी जानी चाहिए, जो अधिक कार्बन डाइऑक्साइड सोखकर ऑक्सीजन छोड़ें। यह हाईवे मुंबई को कोंकण के रास्ते गोवा से जोड़ता है और पर्यटन व स्थानीय कारोबार के लिए महत्वपूर्ण है।

निशिकांत दुबे की मांग....राहुल गांधी की विदेश यात्राओं पर लगे रोक

नई दिल्ली (एजेंसी)। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी के विदेश जाने पर तत्काल रोक लगाने और उनकी संसदीय सदस्यता समाप्त करने की मांग उठा दी है। उन्होंने अपनी मांग के समर्थन में पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा 1955 में लिखे पत्र का हवाला दिया, जिसमें नेहरू ने कथित तौर पर कम्युनिस्ट विचारधारा को देशद्रोह के समान बताया था। झारखंड के देवघर से सांसद दुबे ने लिखा कि नेहरू के शब्दों के अनुसार, क्या राहुल गांधी की संसद सदस्यता खत्म नहीं की जानी चाहिए और उनके विदेश जाने पर रोक नहीं लगनी चाहिए? सांसद दुबे ने नेहरू के हवाले से कहा कि कम्युनिस्ट विचारधारा का मतलब है देशद्रोह, विदेश में जाकर चुनी हुई सरकार के खिलाफ बोलना देशद्रोह है। उन्होंने बताया कि नेहरू ने मशहूर इतिहासकार इरफान हबीब को कम्युनिस्ट विचारधारा से जुड़ा होने के कारण स्कॉलरशिप देने से इंकार किया था। सांसद दुबे ने आरोप लगाया कि विदेशी ताकतों के साथ मिलकर भारत के खिलाफ बोलना और परोक्ष रूप से पाकिस्तान का समर्थन करना देशद्रोह हैं, उन्होंने राहुल गांधी की विदेश यात्राओं पर रोक लगाना पूरी तरह से संवैधानिक होगा। सांसद दुबे ने सवाल किया कि नेहरू द्वारा स्थापित यह मिसाल राहुल गांधी पर क्यों लागू नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कहा, अगर हम नेहरू के पत्र को आधार माना जाएं, जिसमें यह स्थापित किया गया था कि विदेश में देश के खिलाफ बोलने वाला कोई भी व्यक्ति राष्ट्र-विरोधी है, और कम्युनिस्ट विचारधारा को मानने वाले विशेष रूप से खतरनाक राष्ट्र-विरोधी हैं, तब उस आधार पर राहुल गांधी को विदेश जाने से क्यों नहीं रोका जाना चाहिए और उनकी संसदीय सदस्यता क्यों नहीं खत्म की जानी चाहिए?

मायावती ने, भतीजे आकाश आनंद को बसपा से किया बाहर

समधी के संन्यास के बाद लिया बड़ा फैसला

लखनऊ, एजेंसी।
बसपा सुप्रीमो मायावती ने अपने भतीजे आकाश आनंद को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया है। उन्होंने अपने ट्वीट के जरिए यह घोषणा की कि पार्टी के लोगों को यही बेहतर लगता है कि उन्हें पहले दिनांक 3 सितंबर 2026 को जिस प्रकार से पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक के अति-महत्वपूर्ण पद की सभी अहम ज़िम्मेदारियों से मुक्त कर दिया गया था, उसी प्रकार अब उन्हें पार्टी में भी आज से पूरी तरह से फ्री (आज़ाद) कर दिया जाये। अतः श्री आकाश आनन्द पार्टी में अब स्वतंत्र रहना चाहते हैं तो वे स्वतंत्र हैं अर्थात ऐस में अब इनको पार्टी से पूरेतौर से मुक्त कर दिया गया है।
मायावती ने अपने समधी और आकाश आनंद के पिता अशोक सिद्धार्थ के राजनीति से संन्यास लेने के फैसले पर भी कड़ी टिप्पणी की। उन्होंने लिखा, आज श्री अशोक सिद्धार्थ द्वारा राजनीति से संन्यास लेने की घोषणा अति-देर से उठाया गया यह सही क़दम है। मायावती का कहना था कि

अगर यह फैसला पहले ही ले लिया जाता, तो बसपा, बहुजन समाज और बहुजन मूवमेंट के साथ-साथ उनके दामाद आकाश आनंद को भी लगातार विपरीत परिस्थितियों का सामना नहीं करना पड़ता। उन्होंने यह भी कहा कि उन्हें विधानसभा चुनावों और खासकर उत्तर प्रदेश में पांचवीं बार सरकार बनाने की तैयारियों के बीच पार्टी व मूवमेंट के व्यापक हित में कई बार कड़े फैसले लेने की जरूरत नहीं पड़ती। बसपा सुप्रीमो ने पार्टी की अम्बेडकरवादी राजनीति की परंपरा पर जोर देते हुए कहा कि यह बाबा साहेब डॉ. भीमराव अम्बेडकर के पदचिन्हों पर चलने वाली त्याग, तपस्या, संघर्ष और कुर्बानी की पहचान है, जहाँ निजी व पारिवारिक स्वार्थ से दूर रहना सर्वोपरि है। उन्होंने कांशीराम जी की तरह खुद को भी इसी सिद्धांत के प्रति समर्पित बताया और पार्टी के सभी लोगों को निजी व पारिवारिक स्वार्थ और पद की लालसा से ऊपर उठने की सीख दी, ताकि सदियों से शोषित, पीड़ित बहुजन समाज शासक वर्ग बन सके। मायावती ने अशोक सिद्धार्थ के संन्यास के फैसले को देर आये दुरुस्त आये बताया, लेकिन साथ ही उनकी नीयत पर भी सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि अगर अशोक सिद्धार्थ को आकाश आनंद के उज्जवल भविष्य और बसपा व उसके अम्बेडकरवादी बहुजन मूवमेंट के प्रति थोड़ी भी चिंता होती, तो वे बिना देरी किए तुरंत संन्यास की घोषणा कर देते। मायावती के अनुसार, ऐसा कुछ भी न होना यह साबित करता है कि अशोक सिद्धार्थ की नीयत में खोट व अभिलाषा अभी भी पूरी तरह से बरकरार है।

लद्दाख के भविष्य पर मसौदा नहीं आने से भड़के वांगचुक, दी आंदोलन की चेतावनी

-गृह मंत्रालय के साथ लद्दाख पर हुई बैठक रही बेनजीता

नई दिल्ली, एजेंसी।
लद्दाख के भविष्य और लोकतांत्रिक व्यवस्था को लेकर केंद्र सरकार और लद्दाख के प्रतिनिधियों के बीच हुई बैठक में कोई ठोस सहमति नहीं बन पाई, जिससे प्रतिनिधिमंडल ने गहरी निराशा जताई है। गृह मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों और लेह एपेक्स बॉडी(लेब) कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस की सब-कमेटी के बीच करीब चार महीने बाद हुई इस बातचीत में सरकार की ओर से प्रस्तावित लोकतांत्रिक ढांचे का कोई लिखित मसौदा सामने नहीं रखा गया। लद्दाख के एक्टिविस्ट और लेब से जुड़े सोनम वांगचुक ने इसे निराशाजनक बताया। उनके मुताबिक, पिछली बैठक 22 मई को हुई थी और उम्मीद थी कि इस बार सरकार ठोस प्रस्ताव लेकर आएगी।

वांगचुक ने बताया कि बैठक में उन्हें सवालों की एक सूची दी गई और अगली बैठक में चर्चा का आश्वासन दिया गया, जबकि विधानसभा, सीधे परिसीमन और चुनाव जैसे मुद्दों पर पहले भी बात हो चुकी है और इस बैठक में कोई खास प्रगति नहीं हुई। अगली बातचीत अक्टूबर के पहले सप्ताह में कारगिल में होने पर सहमति बनी है, जहाँ प्रतिनिधिमंडल को ज्यादा स्पष्टता और ठोस प्रस्ताव की उम्मीद है। प्रतिनिधिमंडल की मुख्य मांग है कि लद्दाख में जल्द से जल्द लोकतांत्रिक तरीके से चुनी गई विधानसभा स्थापित की जाए और इस प्रस्ताव को संसद के आगामी शीतकालीन सत्र में रखा जाए, ताकि चुनाव और लोकतांत्रिक संस्थाओं के गठन की प्रक्रिया शुरू हो सके। एक सकारात्मक चर्चा का जिक्र करते हुए वांगचुक ने बताया कि बीती घटनाओं में मारे गए और घायल हुए लोगों के लिए मुआवजे पर सरकार ने सहमति जताई है, जिसकी घोषणा जल्द की जाएगी। हालांकि, लोगों के खिलाफ दर्ज मामलों को लेकर अभी स्थिति पूरी तरह स्पष्ट नहीं है। लद्दाख प्रतिनिधिमंडल ने आंदोलन से जुड़े लोगों पर दर्ज मामलों को चरणबद्ध तरीके से वापस लेने के प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया है और सभी मामलों को एक साथ वापस लेने की मांग की है। सरकार ने इस पर विचार करने की बात कही है। वांगचुक के अनुसार, गृह मंत्रालय ने कुछ फैसलों को अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर बताया, जिसके बाद प्रतिनिधिमंडल ने केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन के मुख्य सचिव के सामने अपनी आपत्तियां दर्ज कराईं।

बीजेपी देश की सबसे अमीर पार्टी, विधानसभा चुनावों में मिला 1400 करोड़ का चंदा

नई दिल्ली, एजेंसी।
बीजेपी आज देश के सभी राजनीतिक दलों में सबसे अमीर पार्टी है, इसका खुलासा खुद बीजेपी ने चुनाव आयोग को दिए चुनावी खर्च के ब्योरे में दिया है। चुनावी खर्च के ब्योरे के मुताबिक बंगाल, असम, केरल, तमिलनाडु और पुडुचेरी में विधानसभा चुनावों में बीजेपी को कुल 1,472.8 करोड़ रुपए का चंदा मिला।
बीजेपी द्वारा चुनाव आयोग को दी गई जानकारी के मुताबिक 6 मई, 2026 को चुनाव खत्म होने पर पार्टी का क्लोजिंग बैलेंस बढ़कर 7,627.2 करोड़ रुपए हो गया, जबकि 15 मार्च, 2026 को यह 6,722.6 करोड़ रुपए था। इसमें बीजेपी के सेंट्रल हेडक्वार्टर और संबंधित राज्य की जिला इकाइयां भी शामिल हैं, जिन्हें मिलाकर ये फंड मिला। बीजेपी ने असम, तमिलनाडु और पुडुचेरी में विधानसभा चुनावों पर कुल 160 करोड़ रुपए खर्च किए थे। बीजेपी ने सबसे ज्यादा खर्च असम में किया, जो 96.3 करोड़ रुपए था। इसके बाद तमिलनाडु में 51.6 करोड़ और पुडुचेरी 11.9 करोड़ रुपए खर्च किए। पार्टी के आम प्रचार पर करीब 130.4 करोड़ खर्च किए गए, जबकि 29.6 करोड़ रुपए उम्मीदवारों के एकमुश्त भुगतान पर खर्च हुए। पश्चिम बंगाल और केरल इन दो राज्यों के चुनावी खर्च के आंकड़े चुनाव आयोग ने अभी तक सार्वजनिक नहीं किए हैं। असम के लिए बीजेपी के चुनावी खर्च के ब्योरे के मुताबिक पार्टी ने आम प्रचार पर 76.7 करोड़ रुपए खर्च किए, जिसमें उसकी केंद्रीय इकाई द्वारा खर्च किए गए 23.1 करोड़ रुपए और उम्मीदवारों पर खर्च किए गए 19.5 करोड़ रुपए शामिल हैं। असम में स्टार प्रचारकों की यात्रा खर्च पर 27.3 करोड़, विज्ञापनों पर 37 करोड़, प्रचार सामग्री पर 8.9 करोड़ और राज्य इकाई द्वारा अन्य खर्चों पर 2.3 करोड़ रुपए खर्च किए गए।
रिपोर्ट के मुताबिक उम्मीदवारों को कुल 19.4 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया और उम्मीदवारों के आपराधिक रिकॉर्ड को प्रकाशित करने पर 16.7 लाख खर्च किए गए। तमिलनाडु में बीजेपी ने पार्टी के आम प्रचार के लिए कुल 44.5 करोड़ खर्च करने की मंजूरी दी थी। उम्मीदवारों पर 7 करोड़ रुपए खर्च किए। इन्हीं चुनावों के लिए पहले जारी किए गए अपने खर्च के ब्योरे में कांग्रेस ने कुल 248.6 करोड़ रुपए खर्च होने की जानकारी दी थी।